04 - आरक्षण पर कोर्ट के फैसलों के मायने

05 - आंदोलन का अधिकार और आम आदमी की रोज़ी

A Daily News Magazine

इंदौर

गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2026

06 - एक नोबेल और पुलित्ज़र का छोटा-सा ख्वाब है

07 - कलेक्टर श्री वर्मा ने जनसुनवाई में सुनीं आमजन की समस्याएं

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 12 अंक 33, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

अमित शाह का मिशन पंजाब कितना कामयाब होगा?

अरविंद मोहन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देना वजह हो या कुछ और, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पंजाब चुनाव को लेकर सक्रिय हैं, वह इस अपेक्षाकृत छोटे राज्य के चुनाव को भी काफ़ी दिलचस्प बना देता है। माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी बनाम अमित शाह की खींचतान ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नैया डुबोने का काम किया। इस बार भी पिछले प्रदर्शन को आधार बनाकर दोनों एक दूसरे का कद घटाना और अपना कद बढ़ाना चाहते थे। खैर। पंजाब में अमित शाह ने पिछली बार भी कम मेहनत नहीं की थी और ड्रग के कारोबार को रोकने के नाम पर नेशनल हाइवे से जाने कितने मीटर दूर तक नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने और निगरानी का ज़िम्मा केन्द्रीय बलों को देने जैसे विवादास्पद क़ानूनी बदलाव भी किये। पर जब पार्टी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई तो सारा दोष एनडीए के पार्टनर अकाली दल और इसके एक मंत्री और बादल परिवार के रिश्तेदार विक्रम मजीठिया के सिर मढ़ा गया। पिछली बार 117 सीटों में से बीजेपी को दो और अकाली दल को तीन सीटें मिली थीं।

असल में बीजेपी अभी हाल तक प्रदेश की राजनीति में मुख्य खिलाड़ी रही भी नहीं थी और उसके लिए मैदान में ताल ठोंकना और बड़ी-बड़ी बातें करना भी हल्का लगता था। लेकिन पिछली बार आम आदमी पार्टी (आप) ने जिस तरह से पंजाब को जीता वह बीजेपी के लिए ही नहीं किसी भी नए खिलाड़ी के लिए एक उदाहरण बन सकता है। आप 2014 में एक बार लोकप्रिय होकर पिट चुकी थी और 2017 में उसके हाथ आती बाजी कांग्रेस ने जीत ली थी। पिछली बार आप ने कांग्रेस को पटखनी देकर अपना बदला ले लिया लेकिन पंजाब की राजनीति में दिग्गज रहे कांग्रेस और अकाली दल की गिरावट का बीजेपी कोई लाभ नहीं ले पाई तो सारा नजला अकालियों पर गिरा। उस पर भी यह हुआ कि अकालियों ने विवादास्पद कृषि कानून लाने पर बीजेपी और एनडीए से नाता तोड़ लिया था और अब भी वह मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षा को लेकर संशय में है। पर चुनावी साथी की जरूरत बीजेपी को है तो अकालियों को भी बैसाखी चाहिए। अब सवाल यह बन गया है कि सीनियर पार्टनर कौन होता है अर्थात किसको ज्यादा सीटों पर लड़ने का अवसर मिलता है। बीजेपी को यहां तक ला देना भी अमित शाह और उसके साथी रणनीतिकारों की एक उपलब्धि है।

और इसको असली ताक़त लोकसभा के पिछले चुनाव के नतीजों से मिली है जो बीजेपी के लिए किसी के अनुमान से बेहतर रहे हैं। बीजेपी को विधानसभा की 23 सीटों पर बढ़त मिली तो शिरोमणि अकाली दल को मात्र नौ स्थानों पर। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 37 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली तो आप को 33 सीटों पर। जाहिर है इस रिजल्ट के आधार पर पंजाब की लड़ाई अभी खुली लगती है। और इसी आधार पर इस बार बीजेपी अकालियों से ज्यादा सीटों की बात चला रही है। पर कुछ बातें अमित शाह और बीजेपी के रणनीतिकारों को ध्यान में रखनी चाहिए। यह चुनाव लोकसभा का नहीं, विधानसभा का है और इसमें बीजेपी के पास मोदी जी जैसा कोई चेहरा नहीं है।

अनेक कारणों से बीजेपी का संगठन अभी गाँव गाँव तक नहीं है और सिखों का वोट पाना उसके लिए खासा मुश्किल है। अकालियों के संग लड़ने पर भी यही देखने में आया है कि मोर्चा के अकाली उम्मीदवार को तो हिन्दू वोट मिल जाते हैं लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को सिख वोट नहीं मिलते। दूसरी चीज बीजेपी द्वारा निरंतर अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके बाहरी लोगों- जिनमें फ़िल्म वालों, पूर्व नौकरशाहों और दूसरे दलों से आए नेताओं का अनुपात बहुत ज़्यादा है, को चुनाव में अवसर देना भी है। ऐसे लोग केंद्र में मंत्री तक बने हैं जबकि स्थानीय कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने तक रह गए।

जानी मानी हस्तियों को आखिरी वक्त टिकट देने की बात अभी छोड़ दें तो बीजेपी और इसके सूत्रधार अमित शाह ने काफी सारे नेता दूसरे दलों से तोड़े हैं। सबसे ताजा और बड़ा खेप तो राघव चड्ढा के नेतृत्व में आप के सांसदों को तोड़ने का है।

अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे पुराने कांग्रेसी दिग्गज इधर आकर न कुछ कर पाए और न कुछ पा सके लेकिन अभी भी मनीष तिवारी से लेकर कई कांग्रेसी दिग्गजों के पाला बदलने की चर्चा उड़ती रहती है। कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है और केन्द्रीय नेतृत्व जिस तरह बेपरवाह रहता है उसमें तय मानिए कि अभी कई विकेट गिरेंगे। और अगर कांग्रेस संभलकर लड़ी तो उसके लिए अपना खोया प्रदेश हासिल करके का अवसर है। उसके पास नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की फौज है और समाज के हर वर्ग में पैठ भी है। बात सिर्फ भरोसा बनाने की है और यह कम बड़ी शर्त नहीं हैं। और दूसरे दलों से लोग तोड़ने में बीजेपी ने अकाली दल को भी निशाना बनाया जिसके एक बड़े नेता मनजीत सिंह बादल को उसने अपनी ओर कर लिया है।

अभी तो अमित शाह और बीजेपी की केंद्र सरकार के निशाने पर आप है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के पहले की दिल्ली की स्थिति को याद कर सकें तो आपको वही दृश्य पंजाब में दोहराया जाता दिखेगा। अब आप के लोग कोई दूध के धुले हों और भगवंत मान की सरकार ने कोई झंडे गाड़ दिए हों, यह नहीं है, लेकिन खुद मान साहब और उनके साथियों के साथ पिछले कुछ समय से केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से जो व्यवहार हो रहा है, वह अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येन्द्र जैन जैसों के साथ चले मामलों जैसा ही दिखाता है। यहां कोई नई शराब नीति भी नहीं बनी है और न ठेका देने में संदेहास्पद तरीकों का आरोप है। पर जिस तरह भगवंत मान को विदेश से आने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर ज्यादा खरीद और अघोषित सामान रखने के नाम पर पकड़ा गया वह विशुद्ध अपमान था और किसी अन्य मुख्यमंत्री के साथ ऐसे व्यवहार की याद आपको नहीं होगी।

हमने देखा है कि जब राघव चड्ढा की अगुवाई में आप के सांसदों को तोड़ने का प्रयास हो रहा था तो वहां भी साम दाम दंड भेद सब उपाय करने की बात सामने आई। एक सांसद महाराज तो जेल भी गए और बाद में सब कुछ बीजेपी के वाशिंग मशीन में धुल गया। अब एंटी इंकम्बेन्सी से जूझ रही आप को कमजोर कड़ी मानकर उसकी घेराबंदी तेज करना और सही मुद्दों पर हमले बढ़ाना तो ठीक रणनीति है लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या इन सबसे बीजेपी पंजाब जीत पाएगी।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.in

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

एक घर बनने के लिए
मैंने एक पेड़ को कटते देखा
किसी ने उसे हत्या नहीं कहा
पेड़ पलाश का था
उस पर फूल खिले थे सिंदूरी
चिड़ियाँ चहचहा रही थीं
भँवरे फूलों का रस चूस रहे थे
तितलियाँ मँडरा रही थीं
एक गिलहरी टहनियों पर
फुदक रही थी
कबूतर का एक जोड़ा भी था
डाल पर बैठा हुआ
पेड़ उन सबका घर था
उस शाम चिड़ियाँ, गिलहरी, कबूतर
सब लौटे और पेड़ को न पाकर
निराश हो परिक्रमा लगाकर
जाने कहाँ चले गए
एक घर के बनने के लिए
कितनों का घर उजड़ा।

– चंद्रशेखर साकल्ले

तूफान 'अर्नब' से आंध्र-ओडिशा में हाहाकार

● 3 लोगों की मौत, 57 हजार लोग किए गए शिफ्ट ● 50 ट्रेनें-21 फ्लाइट रद्द,एमपी-यूपी में भी अलर्ट

विशाखापट्टनम (एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'अर्नब' मंगलवार देर रात 3.30 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। यहां 125 से 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में 3 मौतें हुई हैं। राज्य के 31 घरों को नुकसान पहुंचा। 57 हजार लोगों को शिफ्ट किया गया है। तूफान के कारण 50 ट्रेनें और विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 21 फ्लाइट्स रद्द की गईं। ओडिशा में भारी बारिश के चलते 16 जिलों में स्कूल बंद हैं। यहां 30 हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 4,000 साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। विशाखापट्टनम में रात 27 अक्टूबर की सुबह 8.30 बजे से 28 अक्टूबर की सुबह 3 बजे तक, यानी करीब 18 घंटे में 200 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। यह जुलाई में होने वाली औसत बारिश के डेढ़ गुना से ज्यादा है। यहां जुलाई में औसतन 133 मिमी बारिश होती है।

मछलीपट्टनम से बालासोर तक समुद्र का रौद्र रूप

आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में तेज हवाओं और भारी बारिश से मौसम खराब है। वहीं, ओडिशा के बालासोर स्थित उदयपुर बीच पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पूर्वी तट पर अलग-अलग जगहों के इन हालातों से हम समझ सकते हैं कि चक्रवात का असर केवल एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है। इसी बीच लोग इन लहरों में भी जिंदगी का लुत्फ ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में चक्रवात अर्नब के असर से तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है।

यानम में सड़कों पर गिरे पेड़, राहत कार्य जारी

पुडुचेरी के यानम में चक्रवात की तेज हवाओं की वजह से पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं। रास्ते साफ करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। तूफान के दौरान पेड़ गिरने, बिजली की लाइनें टूटने और सड़कें बाधित होने जैसी घटनाएं राहत एवं बचाव कार्य को चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं। आंध्र प्रदेश के चित्रागुम्मुलुरु में चक्रवात प्रभावित गांव का दौरा किया गया। उन्होंने पुनर्वास केंद्र में पहुंचकर लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही राहत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान तस्वीरों की मदद से हम देख सकते हैं कि कैसी पानी भरा हुआ है और रास्तें में तेज हवाएं चल रहीं हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित आरके बीच पर तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस ने लोगों के बीच पर जाने पर रोक लगा दी है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। ताकि खतरा टाला जा सके।

30 हजार एकड़ क्षेत्र में होगा नियोजित शहरी विकास

सीएम यादव बोले-भविष्य में लगभग 15 टाउनशिप की जाएंगी विकसित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के शहरों को आधुनिक, निवेश-अनुकूल, पर्यावरण-संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य तेजी से किया जा रहा है। वर्ष 2047 तक इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने, 12 से 15 नई टाउनशिप विकसित करने तथा 25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंदौर फ्यूचर सिटी में लगभग 5 हजार एकड़ क्षेत्र में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहर केवल आवासीय क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्र हैं। शहरी विकास को आधुनिक अधोसंरचना, जल सुरक्षा, किफायती आवास और बेहतर जीवन गुणवत्ता से जोड़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में निवेशकों के साथ शहरी विकास एवं अधोसंरचना में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

12 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। औद्योगिक कॉरिडोर, सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और आधुनिक अधोसंरचना के विकास के साथ सेमीकंडक्टर सहित आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश निवेश, उद्योग, तकनीकी विकास और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल संरक्षण एवं उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026 तथा किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026 के ड्रॉफ्ट जारी किए।

स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनें टकराईं, 39 की हुई मौत

● एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी

मैड्रिड (एजेंसी)। स्पेन में बुधवार को दो हाई-स्पीड ट्रेनें टकरा गईं। स्पैनिश मीडिया के मुताबिक, हादसे में 39 लोगों की मौत की खबर है। स्पेनिश अखबार एल पाइस के मुताबिक, एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर इमरजेंसी मेडिकल टीमें पहुंची हैं। यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे हुआ। हादसे के बाद राजधानी मैड्रिड को दक्षिणी अंडालूसिया क्षेत्र से जोड़ने वाली रेल लाइन बंद कर दी गई। एक ट्रेन सुबह 8 बजे मैड्रिड से सेविल के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान दूसरी ट्रेन उससे टकरा गई। रेल नेटवर्क चलाने वाली कंपनी एडिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ट्रेन हादसे की खबर सुनकर वे सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और हादसे में प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं।

हरदीप सिंह पुरी एमपी से जाएंगे राज्यसभा

एल.मुरुगन के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। यह सीट केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने इस सीट के लिए नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल, एल मुरुगन का कार्यकाल 2030 तक बचा हुआ था। उनके इस्तीफे के बाद एमपी से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी। राज्यसभा सीट खाली होने के बाद अटकलें थीं कि इस बार पार्टी राज्य के ही किसी नेता को मौका देगी। लेकिन फिर से बाहरी को मौका दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। हरदीप सिंह पुरी अभी मोदी सरकार में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और पेट्रोलियम मंत्री हैं। वह भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं।

जल्द आएंगे नामांकन करने भोपाल

गौरतलब है कि एमपी से राज्यसभा के लिए कई नामों की चर्चा चल रही थी। इस रेस में कुछ प्रदेश के भी नेता थे। सोमवार को कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि राज्यसभा के लिए कुछ प्रदेश और कुछ बाहरी नेताओं के नाम का पैनल भेजा गया है। बुधवार को दिल्ली से हरदीप सिंह पुरी के नाम पर मुहर लग गई है। अब जल्द ही उनके नामांकन की तारीख तय हो जाएगी।

लोन की किस्त नहीं चुकाई, एजेंट्स ने किसान को उठाया

● 3 दिन बाद फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लाश मिली, 5 लोग गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नांदेड जिले में 40 साल के किसान चंद्रकांत शिंदे का शव मिला है। शव निजी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मिला। परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि लोन की किस्त नहीं चुकाने पर रिकवरी एजेंट्स ने चंद्रकांत को किडनैप किया था। तीन दिन बाद उनका शव मिला। चंद्रकांत शिंदे नांदेड जिले के मुदखेड़ तहसील के मलकोठा गांव के रहने वाले थे। पत्नी की शिकायत के अनुसार 22 अक्टूबर की शाम को दो अज्ञात लोगों ने उन्हें जबरन एक मोटरसाइकिल पर बैठाया और फाइनेंस कंपनी ऑफिस ले गए। पुलिस ने अभी यह नहीं बताया है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का। नांदेड एसपी के मुताबिक पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें फाइनेंस ऑपरेशन चलाने वाला मुख्य आरोपी असलम भी शामिल है। मामले की जांच के लिए 9 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई।

किसान आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर

किसान आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर है। डेटा के मुताबिक 2023 में पूरे भारत में खेती-किसानी से जुड़े कुल 10,786 आत्महत्या के मामले सामने आए थे। इसमें से अकेले महाराष्ट्र में 4,151 केस थे। इनमें 4690 किसान थे और 6096 खेत मजदूर थे। आंकड़ो के कारण के आधार पर डेटा नहीं देता।

सूखा प्रभावित गांवों में कर्ज की परेशानी

यह घटना नांदेड जिले के कुछ हिस्सों में किसानों की आर्थिक परेशानी के बीच हुई है। जिले के कई गांवों में सूखे जैसी स्थिति बताई जा रही है। डीएम से पूछा गया कि क्या सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों से लोन वसूली को लेकर फाइनेंस कंपनियों के लिए कोई खास गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हालांकि, जिला कलेक्टर के साथ बैठक की गई है। डीएम ने कहा, अगर कहीं गैरकानूनी तरीके से लोन वसूली हो रही है, तो नागरिक सामने आएं। उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जयकुमार उर्फ भैया भगवान गायकवाड़ (22), शेख आमिर शेख साहेब हुसैन (25), इमरान खान शाहबाज खान (40) और शेख मुदस्सिर शेख खादीर (24) को गिरफ्तार किया है।

यूपी में जल्द बनेगा 90 किमी लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे

● भूमि अधिग्रहण शुरू, गंगा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा

फतेहगढ़ (एजेंसी)। गंगा एक्सप्रेस-वे व आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जिले में बनने वाले लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण जल्द शुरू होगा। प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में निर्माण एजेंसी चयन के बाद तीन वर्ष में कार्य पूरा कराने का निर्णय लिया गया है। निर्माण एजेंसी पांच वर्ष तक एक्सप्रेस-वे का अनुरक्षण करेगी। जिले में करीब 90 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है। इसे हरदोई जनपद के सवायजपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे व दूसरी ओर इटावा में कुदरेल के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए कनेक्टिविटी रूट भी मिलेगा। जिले में बनने वाले लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए प्रशासन ने जमीन अधिग्रहित करने को विशेष कैंप लगवाकर करीब 90 प्रतिशत जमीन का बैनामा करा लिया है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

इजराइल में उलटफेर, रुझानों में नेतन्याहू गठबंधन आगे

ओपिनियन पोल में हार का अनुमान था, ट्रम्प बोले-मेरे समर्थन से माहौल बदला

तेल अवीव (एजेंसी)। इजराइल में संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब तक 76.8त्न वोटों की गिनती में नेतन्याहू गठबंधन 54 सीटों के साथ आगे है। वहीं, गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। अरब पार्टियों के जॉइंट लिस्ट और राअम पार्टी को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इजराइली संसद में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 सीटें जरूरी हैं। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार का अनुमान जताया गया था। चुनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने नेतन्याहू को मिली बढ़त का श्रेय लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उनके समर्थन के बाद चुनाव का माहौल बदल गया। ट्रम्प के मुताबिक, पहले नेतन्याहू की हार का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब मुकाबला बराबरी का हो गया है और वे जीत भी सकते हैं। जॉइंट लिस्ट गठबंधन के अध्यक्ष यूसुफ जबरीन ने कहा है कि उनका गठबंधन सत्ता में बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सरकार को हटाने की कोशिश करने वाली किसी भी पार्टी को उनसे बात करनी होगी। जबरीन ने कहा कि इजराइल के सामने दो रास्ते हैं- यहूदी वर्चस्व को जारी रखना या यहूदियों और अरब नागरिकों के बीच सहयोग कायम करना। अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों- जॉइंट लिस्ट और राअम को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें जॉइंट लिस्ट को 13 और राअम को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं।

लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरे भाजपा नेता

- पटना में खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संभाला मोर्चा

पटना (एजेंसी)। पटना में भाजपा की ओर से बुधवार को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। पदयात्रा शुरू होने से पहले वह मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम

के लिए गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। पदयात्रा कारगिल चौक से शुरू होकर मौर्या होटल के पास स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा तक जाएगी। भाजपा ने इस आयोजन के जरिए लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर जनता के बीच अपना पक्ष रखने की तैयारी की है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की ओर से देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की गई है।

आतंकी साजिश थी यहूदी प्रार्थनास्थल के पास आगजनी

- केरलम का मामला, हैंडलर के इशारे पर लगाई गई थी आग
- हैंडलर को बड़े टारगेट के लिए खुद को साबित करना था

कोच्चि (एजेंसी)। केरलम के कोच्चि में ऐतिहासिक यहूदी सिनागॉग (प्रार्थनास्थल) के सामने 12 अक्टूबर को हुई आगजनी को पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा बताया है। पुलिस के मुताबिक, 32 साल के आरोपी एबिन पॉल ने यह आग लगाई थी। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश कुमार ने कहा कि 12 अक्टूबर की सुबह किया गया हमला एक टेस्ट केस था। आरोपी को पहले कोच्चि में खुद को साबित करने के लिए कहा गया था। इसी के चलते पॉल ने पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद अपने मोबाइल पर घटना का वीडियो भी बनाया था।

परिवार ने कहा- डिप्रेशन का मरीज है पॉल

पॉल एर्नाकुलम जिले में कोलेनचेरी के पास पुथेनक्रूज़ के पास वदयाम्पडी का रहने वाला है। वह एक डिजाइन ग्रेजुएट है। पॉल के परिवार ने मुताबिक, वह डिप्रेशन का इलाज करवा रहा था और घर से डिजाइन का काम भी करता था। पॉल अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन से फोरेंसिक रिजल्ट्स निकाले हैं, जिससे बैन आतंकवादी संगठन के हैंडलर के बारे में और डिटेल्स पता चली हैं। कमिश्नर ने कहा- फिलहाल हम और जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बड़े आतंकी साजिश से जुड़ी जानकारियों की जांच की जा रही है।

क्रिप्टोकरेंसी से भुगतान, टेलीग्राम पर आ रहे थे 'बॉस' के निर्देश

कमिश्नर कुमार ने आगे बताया कि आरोपी को एक हैंडलर निर्देश दे रहा था और उसे क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भुगतान किया जाता था। आरोपी को टेलीग्राम पर 'बॉस' नाम से दर्ज संपर्क से निर्देश मिलते थे। आरोपी ने पूछताछ में 'विक्रम' नाम के व्यक्ति का जिक्र किया है। पुलिस दोनों की पहचान की पुष्टि कर रही है। आरोपी के पुणे में पढ़ाई और बैकग्राउंड से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल हो रही है। पुलिस जनवरी और मार्च में हुई 3 अन्य आगजनी की घटनाओं से भी जोड़कर जांच कर रही है।

भारत और अमेरिका के बीच बड़ा रक्षा समझौता

- राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की बातचीत

मनीला (एजेंसी)। अमेरिका और भारत के बीच 10 वर्षों के लिए जो डिफेंस प्लान पिछले साल तैयार किया गया था उसकी समीक्षा की गई है। फिलीपींस के मनीला में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच 10 सालों के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क में आए डेवलपमेंट की समीक्षा की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य तकनीक और हथियारों के संयुक्त उत्पादन को लेकर बात की गई है। फिलीपींस के सेबू में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और नये क्षेत्रीय सुरक्षा

चुनौतियों को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल दोनों देशों के बीच इस डिफेंस फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए गये थे। इसका मकसद दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। यूएस-इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप पर पिछले साल 31 अक्टूबर को राजनाथ सिंह व हेगसेथ ने दस्तखत किए थे।

बैलेट पेपर से हुए चुनाव, कांग्रेस कितनी सीटें जीती!

- एमएलसी चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि चार बड़े राज्यों में एमएलसी की 28 सीटों पर चुनाव हुए और मतदान बैलेट पेपर यानी मतपत्रों के जरिए कराया गया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं। पीएम मोदी की इस पोस्ट में चुनाव के तरीके और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया है। इन चार राज्यों के चुनाव में अलग-अलग दलों के बीच मुकाबला हुआ है। उपलब्ध नतीजों और रुझानों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी सामने आया है।

बीजेपी काशी हारी, यूपी की 5 सीटें जीती- चार राज्यों की 28 एमएलसी सीटों के नतीजों में बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां भाजपा के पांच बार के एमएलसी नवल किशोर यादव समेत चार सिटिंग एमएलसी चुनाव हार गए। जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर विधान परिषद में खाता खोला। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 5 सीटों पर कब्जा किया, जबकि वाराणसी शिक्षक सीट सपा के खाते में गई।

भाजपा 30 साल बाद पटना टीचर सीट हारी, आरजेडी जीती

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों में से 4 शिक्षक निर्वाचन सीट का रिजल्ट आ चुका है। पटना शिक्षक सीट पर 30 साल बाद बीजेपी की हार हुई है। नवल किशोर को राजद के डॉ. संजीव ने 1057 वोटों से मात दी है। वहीं तिरहुत शिक्षक सीट से बीजेपी के नरेन्द्र सिंह 600 वोटों से जीते। सारण शिक्षक सीट से बीजेपी के बागी और निर्दलीय राहुल राज ने 1815 वोट से जीत दर्ज की है। दरभंगा में जनसुराज के सुरेश प्रसाद राय ने जीत दर्ज की है। तिरहुत स्नातक सीट से वंशीधर लगातार आगे चल रहे हैं।

कर्नाटक- कांग्रेस हारी विपक्ष ने चारों सीटें जीतीं

कर्नाटक में एमएलसी की चार सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस ने कांग्रेस से एक सीट छीन ली, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने अपनी तीनों सीटें बरकरार रखीं। बेंगलुरु शिक्षक सीट पर भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे जेडीएस उम्मीदवार एपी रंगनाथ ने कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी पुट्टन्ना को 908 वोटों से हराया। पुट्टन्ना को 9,902 वोट मिले, जबकि रंगनाथ को 10,810 वोट मिले। उत्तर-पूर्व शिक्षक सीट पर भाजपा के मौजूदा एमएलसी शशिल जी. नामोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर को हराया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नामोशी ने इस सीट पर लगातार पांचवीं बार जीत दर्ज की है। नामोशी को 15,596 वोट मिले, जबकि मत्तूर को 12,299 वोट मिले।

नसीरुद्दीन ने मोदी सरकार को बताया 'नाजायज हुकूमत'

- वीडियो में कहा- हूं मैं दिमागी नक्सल, टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर से छात्रों के लिए आवाज उठाई है और सरकार से सवाल किया है।

दिल्ली में यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल से एक आंदोलन शुरू किया, जो अब फैलता जा रहा है। एक्टर ने इससे पहले, कोलकाता के छात्रों के लिए भी आवाज उठाई थी। अब, वो फिर से बोल पड़े हैं। नसीरुद्दीन शाह ने सरकार से कहा कि वो खुद को दिमागी नक्सल मानते हैं, तो क्या। वो कहते हैं, मैं फख्र के साथ कहता हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं।

नसीरुद्दीन शाह छात्रों के लिए खड़े

उन्होंने आगे कहा, टुकड़े-टुकड़े गैंग अगर इस मुल्क में कोई है, तो वो ये नाजायज हुकूमत है और मैं इस हुकूमत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और क्या-क्या करोगे तुम। हमारे मुल्क के नौजवानों की हिम्मत को तोड़ने के लिए शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने के लिए और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए, कितना करोगे। तुम और तुमने अपने इर्द-गिर्द जो बेवकूफ, बेईमानों की पलटन इकट्ठी की है, कहां तक जाओगे। उन्होंने आगे कहा, पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट और अब जामिया मिलिया...क्या-क्या करोगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दीवाली गिफ्ट

डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की ओर से दीवाली से पहले ही बड़ा गिफ्ट मिल गया है। देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी के साथ अब यह 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले को अपनाया है। इस बढ़ोतरी पर करीब 10,016 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डीए और डीआर की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के एरियर का भुगतान मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक 18,000 रुपये है तो उसे 60 फीसदी के हिसाब से 10,800 रुपये महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा था।

6वें और 5वें वेतन आयोग वालों को भी राहत

सरकार ने 6वें और 5वें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ये बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। महंगाई भत्ते के अलावा कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना- इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

भोपाल में 700 केजी एनालॉग पनीर जब्त

मुरैना से आ रहा था, ट्रेन से उतारते ही दबोचा

भोपाल। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर से 7 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया गया। यह ट्रेन के जरिए मुरैना से यहां लाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार रात 2 बजे यह कार्रवाई की। 700 किलो से अधिक एनालॉग पनीर की कीमत 2.5 लाख रुपए है। विभागीय अधिकारियों ने बिल्टी और बिल के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई कर दी है। बुधवार सुबह तक कार्रवाई

जारी है। मप्र में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद यह पहली कार्रवाई है। जांच कर रही टीम अफसरों की टीम यह पता लगा रही है कि पनीर की सप्लाई कहां होने वाली थी? किस होटल, रेस्टोरेंट या डेयरी पर यह पनीर जाने वाला था। इसके बाद संबंधित के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे एमपी में प्रतिबंधित है एनालॉग पनीर करीब तीन महीने पहले सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया था। बता दें कि एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कम कीमत के कारण बाजार में इसकी खपत तेजी से बढ़ी है।

मानवाधिकार आयोग ने जताई थी नाराजगी

एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर तीन महीने पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने भी नाराजगी जताई थी। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखने का फैसला किया था। इसी बीच सरकार ने पूरे प्रदेश में इस तरह के पनीर पर रोक लगा दी थी। बावजूद भोपाल में 7 क्विंटल एनालॉग पनीर खपाने का मामला सामने आया है।

पायलट मच्छार को यूएई का बड़ा सम्मान

राष्ट्रपति ने गले लगाया, दुबई प्रिंस ने की तारीफ कहा- वे हमारी पहचान हैं, प्लेन क्रैश रोका था

अबू धाबी (एजेंसी)। यूएई ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट को क्रश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को 'जायद II- फर्स्ट क्लास' से सम्मानित किया। इस दौरान UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मच्छर को गले लगाया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने स्मित को अपने देश की पहचान बताया। जायद-II, UAE के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। फ्लाईदुबई फ्लाइट के पायलट मच्छर ने 30 सितंबर को प्लेन क्रैश कराने की कोशिश नाकाम कर दी थी। यह प्लेन दुबई से तेल अवीव जा रही था। इस दौरान को-पायलट ने उन पर हमला कर दिया था। राष्ट्रपति बिन जायद ने फ्लाइट के क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया। इस दौरान UAE के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम भी मौजूद थे। UAE के नेताओं ने कैप्टन मच्छर और क्रू के सदस्यों की हिम्मत और जिम्मेदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी क्रू ने यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कैप्टन स्मित मच्छर ने हिम्मत, जिम्मेदारी और इंसानी जान की परवाह करने की मिसाल पेश की। हमें गर्व है कि वे हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे देश की कहानी का हिस्सा हैं और श्र की पहचान का हिस्सा हैं। कैप्टन मच्छर जब चोटों का इलाज करा रहे थे, तब दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कैप्टन की हिम्मत और लोगों की जान बचाने के प्रयासों की तारीफ की थी।

को-पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था

30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट ञ्ं1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान विमान के को-पायलट ने कॉकपिट में कैप्टन मच्छर पर हमला कर दिया। हमले में कैप्टन घायल हो गए। उन्होंने बताया था कि को-पायलट ने सिर पर कई वार किए। को-पायलट ने विमान को गिराने की कोशिश में कैप्टन पर कॉकपिट में ही मौजूद इमरजेंसी कुल्हाड़ी से हमला किया था। इस दौरान मच्छर ने विमान से हाईजैक का संकेत भी भेजा था।

भूजल में गिरावट, इंदौर जिले में निजी बोरिंग पर रोक, मशीनें जब्त होंगी, जेल व जुर्माना

इंदौर। कम बारिश और भूजल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी व अशासकीय नलकूपों की खुदाई पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। प्रतिबंध तोड़कर बोरिंग करने या इसकी कोशिश करने पर मशीनें जब्त की जा सकेंगी और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, वर्ष 2026 में जिले में औसत से काफी कम बारिश हुई है। वहीं, भूजल के अत्यधिक दोहन से पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। नए निजी बोरवेल की खुदाई जारी रहने पर आने वाले दिनों में पेयजल संकट गहरा सकता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से जुड़े कार्यपालन यंत्री और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री की जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। अनुमति केवल पंजीकृत एजेंसियों को मिलेगी। सरकारी योजनाओं के तहत होने वाली नलकूप खुदाई को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके लिए अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण- प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर नए खोदे गए निजी नलकूपों और पहले से मौजूद अन्य निजी जल स्रोतों का अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण किया जा सकता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। अब जिले में निजी बोरिंग कराने वालों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।

कम बारिश के कारण से कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया

यांत्रिकी विभाग के शहरी और ग्रामीण अधिकारियों की अनुशंसा पर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत यह प्रतिबंध लगाया है।

अवैध बोरिंग पर जेल, जुर्माना

आदेश के पालन के लिए राजस्व, पुलिस और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली या नलकूप खनन की कोशिश करने वाली मशीन जब्त की जा सकेंगी। नियम तोड़ने पर अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत 2,000 रुपये तक का जुर्माना, 2 साल तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

विशेष अनुमति से ही बोरिंग- आपात और अपरिहार्य परिस्थितियों में संबंधित अपर कलेक्टर निर्धारित शर्तों के साथ नई बोरिंग की अनुमति दे सकेंगे। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के लोक स्वास्थ्य

'डॉग फेस्ट' में 200 से अधिक पेट्स आए

इंदौर। 'डॉग फेस्ट इंडिया : इंदौर एडिशन' का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 200 पेट्स और 800 से अधिक पेट लवर्स एवं शहरवासियों ने भाग लिया। 30 से अधिक डॉग ब्रीड्स की मौजूदगी, आकर्षक प्रतियोगिताओं और पेट इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न ब्रांड की गतिविधियों ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बेस्ट ऑफ ब्रीड, बेस्ट डॉग इन शो और बेस्ट पपी जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में विभिन्न नस्लों के डॉग ने हिस्सा लिया और विजेताओं को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शो में प्रोफेशनल प्रोटेक्शन डॉग एवं डॉग एजिलिटी डेमोंस्ट्रेशन विशेष आकर्षण रहे। पेट फैशन शो, पेट प्ले ज़ोन, फोटो बूथ और विभिन्न पेट ब्रांड के स्टॉल्स ने आयोजन को और भी मनोरंजक बनाया। कार्यक्रम में इंदौर के युवाओं, परिवारों और पेट लवर्स ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पेट्स के लिए विशेष सुविधाओं, स्वास्थ्य जांच, विभिन्न गतिविधियों और बेहतर आयोजन व्यवस्थाओं के चलते डॉग फेस्ट इंडिया शहर के सबसे पसंदीदा पेट आयोजनों में से एक बनकर उभरा।

मास्टर प्लान सड़क के लिए जमीन मुक्त

इंदौर। मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित आरडब्ल्यू-2 सड़क निर्माण की राह में आ रहे अतिक्रमणों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में इंदौर विकास प्राधिकरण ने गांधीनगर चौराहे से दिलीप नगर तिराहे तक अतिक्रमण हटाकर करीब 20 हजार वर्गफीट भूमि मुक्त कराई। कार्रवाई के दौरान सड़क मार्ग में बने 6 ढाबे और 4 गुमटियों सहित कुल 10 संरचनाएं हटाई गईं। यहां 75 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य सड़क निर्माण का रास्ता साफ करना और मास्टर प्लान के अनुरूप प्रस्तावित मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करना है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, इंदौर विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही। तीनों विभागों ने आपसी समन्वय से कार्रवाई को अंजाम दिया। भूमि मुक्त होने से प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

इंदौर में न्यूनतम पारा 16.5 डिग्री पर

इंदौर। मौसम में ठंडक की आहट के बावजूद शहरवासियों को दिन में गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। सुबह जल्दी और देर रात हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में पंखे और कूलर की जरूरत बनी हुई है। मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में करीब डेढ़ डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ है। बुधवार सुबह शहर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान हवा की गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई। दृश्यता सामान्य बनी हुई है। फिलहाल सुबह-रात की ठंडक और दिन की गर्मी के कारण मौसम का मिला-जुला मिजाज बना हुआ है।

बुलेट सवार ने स्कूटी से दंपती को गिराया

इंदौर। तिलक नगर थाना क्षेत्र में बुलेट सवार युवक पर दंपती का पीछा कर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, स्नेहलतागंज निवासी मयंक जैन पत्नी जूली के साथ स्कूटी से जा रहे थे, तभी अंकित जैन ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। आरोप है कि उसने पहले मयंक और फिर उनकी पत्नी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। दंपती के नारायणी अस्पताल के सामने पहुंचने पर आरोपी ने पीछा कर स्कूटी में लात मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। इसके बाद आरोपी ने महिला का गला दबाया और मारपीट की। राहगीरों के जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ब्राउन शुगर लाकर इंदौर में बेचता रहा

इंदौर। शहर में नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एरोड्रम पुलिस ने स्कीम-155 के पास एक खेत से धर्मेंद्र जाधव को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 12.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी कीमत 1.28 लाख रुपए बताई गई है। थाना प्रभारी मनोज सेंधव के नेतृत्व में पुलिस टीम संदिग्ध स्थानों पर जांच कर रही थी। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी धर्मेंद्र पिता ओमप्रकाश जाधव, निवासी नंदबाग, को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, वह आगर-मालवा से ब्राउन शुगर लाकर इंदौर के विभिन्न इलाकों में बेचता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में चोरी, मारपीट, डकैती की योजना और मादक पदार्थों से जुड़े मामले भी दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चाकू लेकर घूम रहा बदमाश गिरफ्तार

इंदौर। शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छत्रीपुरा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 34.5 इंच लंबा लोहे का दोमुंहा खटकेदार और नुकीला डिजाइनर चाकू बरामद हुआ। थाना प्रभारी द्वारा गठित विशेष दल को सूचना मिली थी कि एमओजी लाइन स्थित चिंतामन हनुमान मंदिर के पास एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर निखिल उर्फ प्रिंस, निवासी भीम नगर, को पकड़ा। तलाशी में उसकी जींस की जेब से चाकू मिला। पुलिस ने आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एएसआई दीपेश गोराना, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र पाठक और आरक्षक अरुण सिंह चौहान सहित पुलिसकर्मियों की भूमिका रही।

2 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त

इंदौर। दीपावली से पहले अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एरोड्रम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 60 फीट रोड स्थित राधिका आइसक्रीम पार्लर की तलाशी में करीब 2 लाख रुपए कीमत के पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने दुकान संचालक सागर नवीन (38), निवासी पल्हर नगर को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी मनोज सेंधव के अनुसार, पुलिस टीम पटाखा लाइसेंसधारियों के सत्यापन और गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से पार्लर में अवैध पटाखे रखे होने की सूचना मिली। तलाशी में 50 सफेद बोरियां मिलीं। प्रत्येक बोरी में 48 डिब्बे और हर डिब्बे में माचिस बम की 10 डिब्बियां रखी थीं।

जिला जेल का प्रहरी ही तस्करी में धराया, कैदियों को नशा सप्लाई

अंडर गारमेंट और जूतों में चरस और बीड़ी-तंबाकू छुपाई

इंदौर। केंद्रीय व जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था को तार-तार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां जेल की सुरक्षा में तैनात एक प्रहरी ही कैदियों तक नशा पहुंचाने के अवैध कारोबार में शामिल पाया गया। मुख्य द्वार पर हुई सख्ती से जांच के दौरान जब प्रहरी की तलाशी ली गई, तो उसके कपड़ों और जूतों के भीतर से चरस, बीड़ी और तंबाकू के पैकेट बरामद किए गए। इस शर्मनाक घटना के सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है और आरोपी प्रहरी को तत्काल प्रभाव से जेल ड्यूटी से हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात जेल परिसर में उप जेलर राकेश उपाध्याय, चंद्रिका पटेल, नानूराम सोनी और विजय आर्य अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। रात के करीब 2 बजे जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जेल पहुंचा। मुख्य गेट पर तैनात अन्य सतर्क प्रहरियों ने जब नियमानुसार उसकी तलाशी ली, तो उसकी पोल खुल गई। देवेंद्र ने अपने अंडरगारमेंट्स, आंतरिक कपड़ों और जूतों के अंदर शातिर तरीके से चरस, बीड़ी और तंबाकू के पैकेट छिपा रखे थे।

कैमरों की निगरानी में जब्ती - पूरी तलाशी और माल जब्ती की यह कार्रवाई जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। हालांकि इस मामले पर जेल अधीक्षक जवाहर मंडलोई ने केवल बीड़ी और तंबाकू मिलने की बात स्वीकार की है और चरस मिलने से इनकार किया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि बरामद सामान में चरस भी शामिल थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी प्रहरी देवेंद्र चौहान ने कबूल किया है कि वह यह चरस की खेप द्वारकापुरी इलाके के रहने वाले एक नशा तस्कर शुभम नेपाली तक पहुंचाने वाला था, जो फिलहाल इसी जिला जेल में बंद है। इसके अलावा जेल की दूसरी बैरकों में बंद अन्य कैदियों तक भी बीड़ी और तंबाकू सप्लाई करने की उसकी योजना थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए प्रहरी को भारी-भरकम रकम मिलने वाली थी।

पहले भी हुई ऐसी घटनाएं

जेल के भीतर सुरक्षा में सेंध लगने का यह कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी खजराना क्षेत्र के प्रसिद्ध बिल्डर मनोज नागर पर हमला करने वाले आरोपी सोनू खरगोश पर जेल के अंदर ही चाइनीज चाकू से जानलेवा हमला हो चुका है, जिसके बाद उसे तुरंत सेंट्रल जेल में शिफ्ट करना पड़ा था। अब एक जेल प्रहरी के खुद ही प्रतिबंधित नशीले पदार्थ और अवैध सामग्री अंदर ले जाने की इस घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।

इंदौर में 3 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी, 2 ट्रकों में 3 हजार पेटियां जब्त

आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 7 दिन से निगरानी

इंदौर। अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीजीजीआई और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार रात बायपास स्थित पत्थर मुंडला क्षेत्र में 2 ट्रकों को पकड़कर करीब 3,000 पेटी शराब जब्त की। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, अधिकारियों को अवैध शराब की बड़ी खेप ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त टीम ने दोनों ट्रकों की तलाश शुरू की और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। टीमें पिछले 7 दिनों से ट्रकों की निगरानी कर रही थीं। लगातार पीछा करने के बाद मंगलवार रात दोनों ट्रकों को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनमें बड़ी मात्रा में शराब मिली, जिसे जब्त कर लिया गया।

शराब कहां से आई, जांच जारी

कार्रवाई के बाद अब अधिकारी शराब की खेप के स्रोत और उसकी निर्धारित मंजिल का पता लगा रहे हैं। साथ ही, अवैध परिवहन में शामिल लोगों और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क की जानकारी भी जुटाई जा रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दीपावली की खरीदारी के बीच निगम की चेतावनी, बाहर रखा सामान जब्त

मुनादी कर व्यापारियों को चेतावनी, सामान समेटने में लगे दुकानदार

इंदौर। दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को निगम की टीम ने अलग-अलग बाजारों में वाहन से मुनादी कर दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे अपना सामान दुकान के भीतर ही रखें। सड़क या फुटपाथ पर सामान फैलाने वालों का माल जब्त किया जा सकता है। त्योहारी सीजन में कपड़े, सजावटी सामान, बर्तन और पूजा सामग्री खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई दुकानदार बिक्री बढ़ाने के लिए सामान दुकान के बाहर तक सजा रहे हैं। इससे सड़क पर वाहनों के निकलने की जगह कम हो रही है और पैदल चलने वालों को भी परेशानी हो रही है।

चेतावनी से दुकानदारों में हलचल- नगर निगम की मुनादी के बाद कई व्यापारियों ने दुकानों के बाहर रखा सामान समेटकर भीतर रख लिया। दुकानदारों को आशंका है कि कार्रवाई के दौरान माल जब्त होने पर उसे वापस लेने में परेशानी हो सकती है। इसी कारण कई व्यापारियों ने पहले ही सामान हटाना शुरू कर दिया। नगर निगम की मुनादी को इसी व्यवस्था को बनाए रखने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। चेतावनी के बाद भी यदि दुकानदार सड़क या फुटपाथ पर सामान रखकर अतिक्रमण करते हैं, तो उनका माल जब्त किया जा सकता है।

ट्रेन से उतरते समय पैर फिसलने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई

बेटी की शादी होने के दो महीने पहले परिवार पर आघात

इंदौर। रेलवे स्टेशन पर एक मर्माहत कर देने वाली दुर्घटना सामने आई है। यहाँ प्लेटफार्म नंबर 2 पर मंगलवार की रात एक ट्रेन से उतरते वक्त पैर फिसल जाने के कारण एक सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद इजराइल की पटरियों की चपेट में आने से जान चली गई। शहर की एक निजी कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह प्रतिदिन की तरह मंगलवार की रात को अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करने के लिए महू से ट्रेन द्वारा इंदौर पहुँचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, जब ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 पर धीमी गति से आ रही थी, तभी मोहम्मद इजराइल ने उससे नीचे उतरने का प्रयास किया। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वे चलती हुई ट्रेन की चपेट में आ गए।

शरीर पर गंभीर चोटें आईं

इस भीषण दुर्घटना में उन्हें शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मौके पर ही प्राण पखेरू उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी यानी राजकीय रेलवे पुलिस का

दल तुरंत हरकत में आया और मौके पर जा पहुँचा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को रेलवे पटरियों से सुरक्षित बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस देर रात ही शोक में डूबे परिजनों को इस अनहोनी की जानकारी दी। इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी बारीकी से खंगाल रही है।

दो महीने बाद बेटी का विवाह

इस दुखद दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवारजन तुरंत महू से इंदौर के अस्पताल पहुँचे। परिजनों ने बेहद रोते-बिलखते हुए बताया कि मोहम्मद इजराइल के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है, जबकि उनकी लाडली बेटी का विवाह पुणे में निश्चित हुआ था। घर में केवल दो महीने बाद ही बेटी की शादी होनी थी, जिसके लिए परिवार के सभी सदस्य महीनों से जोरों-शोरों से तैयारियां करने में जुटे हुए थे। शादी की खुशियों के बीच अचानक आए इस वज्रपात ने पूरे परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। जीआरपी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है और आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है।

साइबर ठगी के संदेह में 11 आरोपी घेरे में, खातों से 1 करोड़ के लेनदेन

विजय नगर पुलिस की कार्रवाई, छह बैंक खातों की पड़ताल

इंदौर। साइबर ठगी के संदेह में विजय नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में छह बैंक खातों के जरिए करीब एक करोड़ रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 सिम कार्ड, 17 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, तीन कैलकुलेटर इकाइयां, एक हार्ड डिस्क, दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को संदिग्ध बैंक खातों के संबंध में सूचना मिलने पर दिलीप पांडे से पूछताछ की गई। उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस दल प्रिंसेस स्काई बिजनेस पार्क स्थित 'द रैपिड इन्वेस्टर्स' कंपनी के कार्यालय पहुंचा। यहां कंपनी संचालक शुभम शर्मा से पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ग्राहकों से फोन के जरिए संपर्क कर रकम प्राप्त की जाती थी। यह राशि कंपनी के खातों और कथित तौर पर दिलीप पाण्डे के माध्यम से उपलब्ध कराए गए बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इन खातों का इस्तेमाल दूसरे लोगों के नाम पर लेनदेन के लिए किए जाने की आशंका है। कर्मचारियों को प्राप्त राशि के अनुपात में हिस्सा दिए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस इन सभी तथ्यों की जांच कर रही है।

विजय नगर थाने में अपराध क्रमांक 1013/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस बैंक खातों के वास्तविक धारकों, रकम के स्रोत और राशि आगे किन खातों में भेजी गई, इसकी पड़ताल कर रही है। फिलहाल एक करोड़ रुपए का आंकड़ा प्रारंभिक जांच में सामने आए लेनदेन का है। कथित ठगी की वास्तविक राशि और प्रभावित लोगों की पहचान जांच के बाद स्पष्ट होगी।

कमीशन के लालच में खाता

पुलिस ने चेतावनी दी है कि कमीशन के बदले बैंक खाते उपलब्ध कराने या संदिग्ध रकम आगे भेजने वालों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि वे अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, एक बार इस्तेमाल होने वाला गुप्त अंक (ओटीपी) या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को न दें। संदिग्ध लेनदेन की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जांच के दायरे में आए नाम हैं दिलीप पांडे, शुभम शर्मा, एहमद राजा शेख, भरत भूषण कुशवाह, नरेश यादव, विजेन्द्र सिंह, अमित मणी, रमनदीप सिंह भाटिया, नरेन्द्र पाटीदार, अमित चौरसिया और योगेश पटेल।

संपादकीय

अब चीतों का भी अवैध शिकार

अब मध्यप्रदेश में बाघों के बाद चीते भी अवैध शिकारियों के निशाने पर आ गए हैं। यह अपने आप में बेहद गंभीर और चिंताजनक बात है। क्योंकि जहां सरकार देश में चीतों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं उनके गैरकानूनी शिकार की कोशिशें भी बखौफ बढ़ रही हैं। ताजा घटनाक्रम मप्र के शिवपुरी जिले के कूनो अभयारण्य का है, जहां विदेश से भारत लाए गए चीतों में से एक मादा चीता निर्वा की 19 छर्रे लगने से मौत हो गई। यह गोलियां किसने चलाईं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चीते के पोस्टमार्टम में 5 छर्रे मिले हैं। पूरे मामले की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते जांच के लिए उच्चस्तरीय टीम भेजी है। इस टीम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के वन महानिरीक्षक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक और ब्यूरो के क्षेत्रीय उपनिदेशक शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी वन और पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि टीम अपनी जांच और सिफारिशें मंत्रालय को सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के लिए आगे के निर्देश तय किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये चीते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना के तहत भारत लाए गए थे। ताजा घटना ऐसे समय हुई है, जब भारत में चीतों को फिर से बसाने की परियोजना के तहत उनकी संख्या बढ़ाने के साथ उनके संरक्षण और निगरानी पर साल 2022 से पहल शुरू की गई। इस घटना के बारे में मप्र की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन डॉ. समिता राजौरा का कहना है कि केएनजी22 को 25 अक्टूबर को श्योपुर टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के कंपार्टमेंट नंबर 748 के इलाके में घायल हालत में पाया गया था। हमने पूरी कोशिश की उसे बचाने की। शुरुआती एक्स-रे में चीते के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कई फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए थे। इसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया। चीते के शरीर से पांच फायरआर्म पैलेट यानी बंदूक के छर्रे निकाले गए। उन्होंने कहा कि इस घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अभी यह यह जांच का विषय है कि इस चीते का शिकार हुआ है या किसी ग्रामीण ने अपने पशुओं के बचाव में यह सब किया। राजौरा के मुताबिक हर चीते के पीछे एक मॉनिटरिंग टीम है जो लगातार रेडियो कॉलर के सिग्नल के साथ चीते पर नज़र बनाए रखती है। जांच दल इस बात की भी जांच करेंगे कि मॉनिटरिंग टीम को गोली चलने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी और रेडियो कॉलर के सिग्नल को ट्रैक करने में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। वैसे भी मप्र का कूनो, श्योपुर और मुरैना के आसपास के जंगल पहले भी तेंदुओं के कथित शिकार से जुड़ी जांच के केंद्र में रहे हैं। इस साल की शुरुआत में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, इलाके में तेंदुओं की हत्या और उनके अंगों की तस्करी से जुड़े कथित नेटवर्क की जांच की गई थी। इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। वन विभाग के मुताबिक़, केएनजी22 की मौत के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 58 रह गई है। इनमें 52 कूनो नेशनल पार्क, चार गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और दो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में हैं। बहरहाल मादा चीते की हत्या के पीछे कारण भी हो, इसके लिए दोषी व्यक्ति को सख्त सजा दी जानी चाहिए। वरना अवैध शिकारियों के लिए मप्र बाघों की तरह चीतो का भी 'अभयारण्य' बन जाएगा।

आरक्षण पर कोर्ट के फैसलों के मायने

नजरिया

अमित बैजनाथ गर्ग
वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के तहत मिलने वाली सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति दूसरे धर्म में जाने पर हस्तांतरित नहीं होती है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश को गलत ठहराया, जिसमें इस्लाम अपनाने वाले कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि एससी का दर्जा केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत होता है, जिसे सिर्फ सरकार के आदेश से बदला या पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 73 प्रतिशत आरक्षण वाले फैसले को भी असंवैधानिक करार दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य में 73 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग और व्यवस्था को खारिज कर दिया। सरकार ने सीधी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोटा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था, जिससे कुल आरक्षण 73 प्रतिशत (एसटी 20 फीसदी, एससी 16 फीसदी, ओबीसी 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस 10 फीसदी) हो गया था। कोर्ट के अनुसार, आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां या पर्याप्त प्रमाणित आंकड़े नहीं पाए गए। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को लंबित 13 फीसदी पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

इन दो फैसलों के बाद एक बार फिर आरक्षण पर बहस छिड़ गई है। देश में आरक्षण पर बहस मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक भेदभाव और योग्यता के इर्द-गिर्द घूमती है। इस विषय पर समाज में दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला आरक्षण के पक्ष में तर्क है, जिसे सामाजिक न्याय का पक्ष कहकर प्रचारित किया जाता है। इसके समर्थकों का मानना है कि सदियों से जाति-व्यवस्था के कारण दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक शोषण हुआ है। उनका मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य राजनीति, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में इन वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देना

है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। आरक्षण के समर्थक इसे लगातार जारी रखने की बात कहते हैं।

दूसरा पक्ष आरक्षण के विरोध या समीक्षा के तर्क देने वालों का है। उनका कहना है कि आरक्षण का आधार योग्यता और कमजोर आर्थिक पक्ष होना चाहिए। यह किसी भी जाति का हो सकता है। विरोधियों का तर्क है कि चयन का आधार केवल योग्यता होना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण से योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलने में कठिनाई होती है। एक बड़ा वर्ग यह मांग करता है कि आरक्षण जाति आधारित न होकर आर्थिक स्थिति (गरीबी) पर आधारित होना चाहिए, जिससे अमीर आरक्षित वर्ग के बजाय वास्तव में जरूरतमंद गरीबों को लाभ मिल सके। यह सवाल भी उठाया जाता है कि जो परिवार पहले से ही आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ बार-बार क्यों मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को आरक्षण स्वतः ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन कड़वा सच यह है कि कोई छोड़ता नहीं है।

अब बात करते हैं आरक्षण की सबसे पहले मांग की। आजादी से पहले 1882 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष पहली बार सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आनुपातिक आरक्षण की मांग रखी थी। वहीं 1902 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर रियासत में पिछड़े और गैर-ब्राह्मण वर्गों के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू किया था, जिसे आधुनिक भारत में आरक्षण की वास्तविक शुरुआत माना जा सकता है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवॉर्ड की घोषणा की, जिसके तहत दलितों सहित विभिन्न वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तय किए गए। बाद में महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। आजादी के समय डॉ. अंबेडकर और अन्य नेताओं ने समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए विशेष प्रावधानों पर चर्चा की थी। आरक्षण भी उनमें से एक था।

अब बात करते हैं आजादी के बाद देश में आरक्षण की संवैधानिक शुरुआत की। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में संवैधानिक आरक्षण प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हुआ था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी। इंदिरा गांधी और उनके बाद राजीव गांधी की सरकार ने मंडल आयोग की इन सिफारिशों को लागू नहीं किया था। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की। इसके बाद 2019 में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया।

असल में आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े, शोषित और वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थानों और विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के स्तर पर ओबीसी को 27 फीसदी, एससी को 15 फीसदी, एसटी को 7.5 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न संशोधनों और प्रावधानों के अनुसार कुल केंद्रीय आरक्षण 59.50 प्रतिशत है। वहीं ओबीसी और कुछ श्रेणियों में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को इस दायरे से बाहर रखने के लिए क्रीमी लेयर का नियम लागू है, जिसकी वर्तमान में सीमा आठ लाख रुपए वार्षिक आय है। वहीं इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की थी। हालांकि केंद्र सहित तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने 69 प्रतिशत तक आरक्षण देकर विशेष कानूनों के तहत इस सीमा को पार किया है।

असल में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य न्यायालयों की टिप्पणियां गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। इससे पता चलता है कि आरक्षण की वजह से कितनी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो आरक्षण अपने उद्देश्य में असफल रहा है। असल में अब आरक्षण की समीक्षा नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना जरूरी है। न यह जाति के आधार पर हो और ना ही आर्थिक आधार पर। किसी भी तरह के आरक्षण की अब कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह हर जाति और वर्ग के गरीब छात्रों को पूरी तरह निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाया जाए। आरक्षण से बनने वाले नेता और कर्मचारियों को देश देख ही रहा है। दुनिया में कहीं पर भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था को क्यों लागू किया गया है? देश को कमजोर होने से बचाने के लिए आरक्षण को पूरी तरह हटाना जरूरी है। देश पहले है, जातियां और बाकी सब कुछ उसके बाद।

युवा सक्रियता एवं राजनीतिक विशेषणों में उलझा लोकतांत्रिक संवाद

मुद्दा

डॉ. पी. के. बाजपेयी
लेखक समाज वैज्ञानिक हैं।

शब्द केवल शब्द नहीं होते। वे अपने साथ अर्थ, इतिहास और कभी-कभी राजनीतिक संकेत भी लेकर चलते हैं। 'नक्सल', 'अर्बन नक्सल' और अब 'दिमागी नक्सल' जैसे शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। इनके इस्तेमाल ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। सवाल यह है कि 'दिमागी नक्सल' किसी गंभीर सामाजिक-वैचारिक समस्या की ओर संकेत करता है या राजनीतिक विमर्श में असहमति रखने वालों को कठघरे में खड़ा करने का नया मुहावरा बन गया है?

आज इस बहस को समझने के लिए देश के विश्वविद्यालयों, नागरिक अधिकार आंदोलनों और युवाओं के बीच उठ रहे सवालों को भी देखना होगा। काक्रोच जनता पार्टी, आरक्षण हटाओ आन्दोलन और यूजीसी रोलबैक जैसे विरोध प्रदर्शनों ने यह दिखाया है कि नई पीढ़ी केवल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वाली पीढ़ी नहीं है; वह नीतियों, संस्थानों और अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरने का साहस भी रखती है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के व्याख्यानों ने इस बहस को तेज किया है।

प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में बार-बार युवाओं, लोकतंत्र, विकसित भारत और नागरिक भागीदारी की बात करते हैं लेकिन जब युवा सवाल पूछते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं तो ऐसे युवाओं को राष्ट्र-विरोधी, अराजक या 'दिमागी नक्सल' कहकर खारिज कर दिया जाता है।

क्या असहमति अपराध है?

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण असहमति को स्थान देना है। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। किसी नीति पर सवाल उठाना राष्ट्र-विरोध नहीं है। किसी कानून के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करना, विस्थापितों अथवा आदिवासियों के अधिकारों की बात करना, पर्यावरण की रक्षा की मांग करना या मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रश्न उठाना अपने आप में नक्सली मानसिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। काक्रोच जनता पार्टी, आरक्षण हटाओ आन्दोलन और यूजीसी रोलबैक से जुड़े विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के सवालों और तौर तरीकों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है लेकिन उन्हें दिमागी नक्सल करार देना लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करता है। किसी आंदोलन की आलोचना उसके तथ्यों, मांगों और तरीकों के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसके प्रतिभागियों पर राजनीतिक लेबल लगाकर। भारत का संविधान नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र इसलिए लोकतंत्र है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों का एक ही विचार होना आवश्यक नहीं है। यदि 'दिमागी नक्सल' शब्द हर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगे जो सरकार से असहमत है, विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछता है, किसी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करता है या संस्थागत निर्णयों की समीक्षा की मांग करता है, तो यह शब्द समस्या को समझने के बजाय बहस को समाप्त करने का माध्यम बन जाएगा।

राजनीति में लेबल का आकर्षण

राजनीति में लेबल लगाना आसान होता है। इससे जटिल प्रश्नों को घुमाना आसान हो जाता है। किसी व्यक्ति को 'राष्ट्रवादी' या 'राष्ट्र-विरोधी', 'देशभक्त' या 'देशद्रोही', 'नक्सल' या 'गैर-नक्सल' के खानों में रख देना बहस को आसान बना देता है।

एक व्यक्ति किसी सरकारी नीति का विरोध कर सकता है और फिर भी देश के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो सकता है। कोई छात्र किसी विश्वविद्यालयी निर्णय की आलोचना कर सकता है और संविधान में गहरी आस्था रख सकता है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी

अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है और नक्सलवाद का उतना ही विरोधी हो सकता है।

काक्रोच जनता पार्टी और आरक्षण हटाओ आन्दोलन जैसे विरोध प्रदर्शनों को भी इसी व्यापक लोकतांत्रिक संदर्भ में समझना चाहिए। इन संगठनों की मांगों, भाषा और तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें सीधे 'दिमागी नक्सल' कह देना न तो विश्लेषण है और न ही समाधान। इसी तरह यूजीसी रोलबैक के विरोध में उठे सवाल केवल किसी एक अधिसूचना या प्रशासनिक निर्णय तक सीमित नहीं हैं। वे शिक्षा की दिशा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, छात्रों की भागीदारी और नीति-निर्माण में पारदर्शिता से जुड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तर्क और संवाद से दिया जाना चाहिए।

युवाओं का पुनरुत्थान

हाल के वर्षों में युवाओं की सार्वजनिक भूमिका फिर से उभरती दिखाई दे रही है। विश्वविद्यालय परिसरों, नागरिक मंचों और डिजिटल माध्यमों से निकलकर युवा अब नीतिगत बहसों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। वे रोजगार, शिक्षा, फीस, सामाजिक न्याय, संस्थागत स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं।

यह पुनरुत्थान केवल विरोध की राजनीति नहीं है। यह उस पीढ़ी की बेचैनी भी है जो अपने भविष्य को लेकर गंभीर है। वह पूछना चाहती है कि शिक्षा के बाद रोजगार कहाँ है, संस्थानों में अवसर कितने समान हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और नागरिकों की आवाज कितनी सुनी जाती है। युवा अब केवल परीक्षा, नौकरी और निजी जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे इतिहास, समाज, संविधान और सार्वजनिक नीति पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि इस सक्रियता को 'अराजकता' या 'दिमागी नक्सलवाद' कहकर दबाया जाएगा, तो इससे समस्या समाप्त नहीं होगी; बल्कि युवाओं और संस्थानों के बीच अविश्वास बढ़ेगा।

एक बेरोजगार युवा के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे रोजगार मिलेगा या नहीं। एक छात्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसकी फीस, छात्रवृत्ति और शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी। एक शोधार्थी के लिए संस्थागत स्वतंत्रता और निष्पक्ष अवसर महत्वपूर्ण हैं। एक आदिवासी परिवार के लिए जमीन, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री के संदेश और लोकतांत्रिक व्यवहार

स्वतंत्रता दिवस का अवसर केवल सरकारी उपलब्धियों का विवरण देने का अवसर नहीं होता। यह संविधान, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की मूल भावना को याद करने का अवसर भी है। जब प्रधानमंत्री युवाओं से बड़े सपने देखने, नवाचार करने और राष्ट्र-निर्माण में भाग लेने का आह्वान करते हैं, तो उस आह्वान में सवाल पूछने की स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए। राष्ट्र-निर्माण केवल सरकारी योजनाओं का समर्थन करने से नहीं होता; वह नीतियों की समीक्षा, कमियों की पहचान और बेहतर विकल्प सुझाने से भी होता है।

शायद 'दिमागी नक्सल' की बहस हमें उन वास्तविक समस्याओं से दूर कर रही है जिनसे देश का सामान्य नागरिक रोज जूझ रहा है। बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता, किसानों की समस्याएँ, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ता नशा, मानसिक स्वास्थ्य, प्रदूषण और संस्थानों में घटता विश्वास आदि वे समस्याएँ हैं जो नागरिक के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

साथ ही हमें यह तय करना होगा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए कितनी जगह बची रहेगी। मजबूत लोकतंत्र वह नहीं जिसमें सरकार से कोई सवाल न पूछे। मजबूत लोकतंत्र वह है जिसमें सरकार सवालों का जवाब देने में सक्षम हो और नागरिक सवाल पूछने में भयभीत न हों। यदि हमें सचमुच एक मजबूत, समावेशी और लोकतांत्रिक भारत बनाना है, तो हमें सार्वजनिक विमर्श में असहमति को ख़ारिज करने के बजाय पर्याप्त जगह और समुचित सम्मान देना होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

करवा चौथ और साड़ी को लेकर किंकर्तव्यविमूढ़ सिरीमती

व्यंग्य

मुकेश राठौर
लेखक व्यंग्यकार हैं।

पति द्वारा लंबी उमर करवाने के बदले अपनी सगी पत्नी को उपहार स्वरूप साड़ी दिलाने की परम्परा कब शुरू हुई ये तो पक्के से नहीं पता लेकिन इतना तो तय है जबसे करवा चौथ शुरू हुई साड़ी देने का रिवाज़ भी कदाचित उसी समय से शुरू हुआ होगा! साड़ी है गर सिक्के,मूर्ति या बर्तन होते तो पुरातत्ववेत्ता अब तक नदियों के किनारे खोद कर कर बता चुके होते। खैर, करवा चौथ पर पति से और रक्षाबंधन पर भाई से साड़ी प्राप्त करना हर महिला के मौलिक अधिकार जैसा है। साल के बारह महीनों में दो साड़ी तो पक्की समझिये,इस बीच ससुराल या मायके में कोई शुभ प्रसंग आ जाए तो यह आंकड़ा दो से दस हो जाए फिर भी बस कहने का सवाल ही नहीं। पहनने योग्य कपड़ों का व्यापक सर्वे किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश में साड़ियां,पतलून-कमीज से इक्कीसी बल्कि बत्तीसी बैठेगी।

कुल जमा मसला यह कि सिर पर खड़ी करवा चौथ देख हम साड़ी खरीदने शहर गए। उन्हें साड़ी लाने तो मुझे गाड़ी च-लाने के लिए जाना ही था। यूं तो बाजार में साड़ियां ही साड़ियां थी मगर हमें तो बॉम्बे बाजार स्थित 'पहली पसंद' साड़ी शोरूम पर जाना था क्योंकि उसका नाम चलता है। एक बार किसी का नाम चल जाए तो फिर काम कौन देखता है! देखा तो पाया शोरूम में पृष्ठ भाग तो दूर पैर रखने कि जगह नहीं थी,बाहर पार्किंग के हाल भी इससे जुदा न थे। सिरीमती को शोरूम में छोड़ सोचा अभी दस बज रही है इधर बैठे-बैठे क्या करूँगा! कॉलोनी वाली मैडम फोन पर बार-बार प्लॉट देखने का आग्रह करती रहती है आज मौका है और मज़बूरी भी। मैं प्लॉट देखने निकल पड़ा। मात्र हजार रूपये जमा करते ही प्लॉट बुक हो गया। फाइनेंसर भी घात लगाकर हमला करने को तैयार बैठे थे।बताने पर कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं,अतिथि नहीं फिक्समफिक्स तिथि प्रजाति का। फिर क्या था, उन्होंने अठारह लाख फाइनेंस की प्रक्रिया अबूझ मुहूर्त में कर डालीं। सरकारी कर्मचारी को लोन देने से भला कौन मना करेगा! सरकारी आदमी चाँद पर घर बनाना चाहे तो लोन देने वाले मौका देखे बगैर चौका जमा दें। हां कोई गरीब कुटी चाहे तो दो जोड़ी चप्पल घिस जाए। आप सोच रहे होंगे सरकारी आदमी पर इतनी मेहरबानी किसलिए? वह इसलिए कि उसके पैसे को मर नहीं होती,वह मर भी जाए तो भी। वे बोलें सर आज से आप यहां के जमींदार हुए। आपको किस्तों की भी चिंता नहीं,बारह लाख के प्लाट के लिए पंद्रह हजारी दस सालों की किस्त और बात खतम। यकीन मानिये मालूम भी नहीं पड़ेगा। कर्ज किस्तों में चुकाया जाए तो मालूम नहीं पड़ता,फिर बारह के बदले अठारह चले जाए अलग बात है। इधर का काम निपटा तो उप पंजीयक के सामने उपस्थित होकर प्लॉट की रजिस्ट्री भी सम्पन्न करवा लीं। हालांकि इधर लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि सरकारी काम समय मांगता है लगे तो सेवा भी।

बहरहाल,आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास वाली स्थिति से बाहर निकलते ही मुझे सिरीमती की याद आई हालांकि प्लॉट खरीदी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान उनकी याद आती बल्कि सताती रही। याद ही आ सकती थीं कॉल नहीं क्योंकि उनके पास मोबाइल भी तो नहीं था। अब मैंने पहली फुर्सत में पहली पसंद की राह पकड़ी। चलती बाइक पर विचारता रहा करवा चौथ पर उनके द्वारा अपने चाँद को देखने से पहले आज मेरे द्वारा अपने चांद को देखना भयंकर अनुभव रहेगा। पता नहीं बेचारी कहां किस हाल में 'आ जा रे मैं तो कबसे खड़ी इस पार,ये आंखियाँ थक गई पंथ निहार' गुनगुना रही होगी !एक बार लगा शोरूम में बोर होते-होते सिरीमती कहीं किराये से रह रही बोरगांव बुजुर्ग वाली साली साहिबा के घर पैदल ही तो नहीं पहुंच गई !मैं सीधे वहीं पहुंचा,वो वहां नहीं थीं। ऐसा तो नहीं अपने मामाजी के घर बैठी हों! या फिर मेरी मौसी के घर !नहीं,नहीं...सगी बहन के ऊपर सास की बहन को तरजीह सम्भव ही नहीं। मामाजी से फोन पर पता करने पर पता चला वो नहीं आई। इस पूछ परख में शाम होने को आई। अब मेरे मन में भावी अनिष्ट की आशंका गहराने लगी। सोचा इस तरह धुप्पल में लट्ठ चलाने के बजाय पहली पसंद पर ही पहले जाया जाए वहीं से खुलेगा कोई रास्ता। सारे किन्तु-परन्तु मन में लिए मैं वही पहुंचा जहां सुबह उन्हें छोड़ कर आया था। मैंने काउंटर पर बैठे सेठ टाइप आदमी से पूछा सुबह हमारी सिरीमती इधर आई थी साड़ी लेकर यहां से कब निकलीं? 'भाई साहब मैडम जी तो अभी इधर ही है' उसने कहा। महिलाओं की भीड़ में मेरी नजर अपनी महिला पर गई। वो दो साड़ियां हाथ में लिए मेरी ओर लपकी बोलीं बस हो ही गया,ये बताओ इन दो में से कौन सी मुझ पर अच्छी लगेगी?

अब मेरा मन प्लॉट का नामांतरण करवाने का होने लगा, मगर कार्यालयीन समय इजाजत नहीं दे रहा था।

दृष्टिकोण

संध्या अग्रवाल

लेखक साहित्यकार हैं।

आंदोलन का अधिकार और आम आदमी की रोज़ी

त्योहारों के समय यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है। मिठाई की दुकान, कपड़ों का छोटा प्रतिष्ठान, मिट्टी के दीपक बेचने वाला कुम्हार और फूलों की दुकान लगाने वाला विक्रेता-इन दिनों की बिक्री पर उनकी आय का बड़ा हिस्सा निर्भर कर सकता है। यदि रास्ते बंद हों, यातायात बाधित हो या बाजार तक ग्राहक न पहुँच पाएँ, तो नुकसान केवल एक दिन की बिक्री तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवारों के घरेलू बजट, कर्मचारियों की मजदूरी और छोटे कारोबार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी नागरिक को अपनी माँग रखने, प्रशासन से प्रश्न पूछने या सरकार के निर्णय से असहमति जताने के कारण गलत नहीं ठहराया जा सकता।

विरोध प्रदर्शन जीने के अधिकार का हिस्सा है और लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इस देश में विरोध-प्रदर्शन हमेशा होते रहे हैं और उनके लिए पूरा अवसर भी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक, कई बड़े बदलावों की शुरुआत किसी न किसी आंदोलन से ही हुई है। इसलिए विरोध के अधिकार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता; वह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखने तथा वहाँ प्रस्तावित तिरंगा मार्च के संदर्भ में छोटे व्यापारियों की आजीविका का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। 16 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और उनके परिवारों की कठिनाइयों पर चिंता जताई। अदालत ने यह भी कहा कि यदि प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों को अनुचित नुकसान पहुँचता है और कार्रवाई गैरकानूनी पाई जाती है, तो मुआवजे सहित उचित कदम उठाए जा सकते हैं। यह प्रसंग एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है–जब दो लोकतांत्रिक अधिकार आमने-सामने आ जाएँ, विरोध का अधिकार और रोज़ी-रोटी का अधिकार, तो उनके बीच संतुलन कैसे बने?

किसी राजनीतिक दल या संगठन के लिए आंदोलन अपनी माँगों को सामने रखने और जनसमर्थन जुटाने का माध्यम हो सकता है। नेताओं के भाषण होते हैं, नारे लगते हैं और समाचार माध्यमों में चर्चा होती है। लेकिन इसी दौरान सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यक्ति, छोटी दुकान के मालिक, रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर किस स्थिति से गुजरते हैं, इस पर भी ध्यान देना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। उनके लिए आंदोलन के दौरान कामकाज प्रभावित होने का अर्थ उस दिन की कमाई का नुकसान हो सकता है, जिससे परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं।

त्योहारों के समय यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है। मिठाई की दुकान, कपड़ों का छोटा प्रतिष्ठान, मिट्टी के दीपक बेचने वाला कुम्हार और फूलों की दुकान लगाने वाला विक्रेता–इन दिनों की बिक्री पर उनकी आय का बड़ा हिस्सा निर्भर कर सकता है। यदि रास्ते बंद हों, यातायात बाधित हो या बाजार तक ग्राहक न पहुँच पाएँ, तो नुकसान केवल एक दिन की बिक्री तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवारों के घरेलू बजट, कर्मचारियों की मजदूरी और छोटे कारोबार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी नागरिक को अपनी माँग रखने, प्रशासन से प्रश्न पूछने या सरकार के निर्णय से असहमति जताने के कारण गलत नहीं ठहराया जा सकता। कई बार आंदोलनों ने वास्तविक समस्याओं को सामने लाने और समाधान का रास्ता खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हर आंदोलन को अनावश्यक या जनविरोधी कहना उचित नहीं होगा। प्रश्न आंदोलन करने के अधिकार का नहीं, बल्कि इस बात का है कि उसे किस तरह प्रभावी, शांतिपूर्ण और दूसरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

जब किसी प्रदर्शन से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका हो, तब उसके आयोजकों और प्रशासन को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे विरोध की आवाज भी प्रभावी ढंग से उठ सके और आम नागरिकों की कठिनाइयाँ भी कम हों। जहाँ सड़क पर प्रदर्शन आवश्यक हो, वहाँ मार्ग, समय, यातायात और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था पहले से तय की जा सकती है। आयोजक यदि अपने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील करें तथा प्रशासन भी संवाद के माध्यम से सहयोग करे, तो टकराव की आशंका कम की जा सकती है। इससे विरोध का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जनजीवन पर पड़ने वाले असर को सीमित करने में मदद मिलेगी।

आंदोलन के दौरान पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की भूमिका भी चुनौतीपूर्ण होती है। उन्हें भीड़ को नियंत्रित करने, यातायात चलाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों, दोनों को चोटें आती हैं। ऐसी घटनाओं में केवल एक पक्ष की पीड़ा देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी जाँचना चाहिए कि टकराव कैसे शुरू हुआ, बातचीत के क्या प्रयास किए गए, बल प्रयोग की आवश्यकता कितनी थी और क्या उसका इस्तेमाल निर्धारित सीमाओं के भीतर हुआ। जवाबदेही का सिद्धांत सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

राजनीतिक आयोजनों में एक और प्रश्न उठता है– आंदोलन का उद्देश्य क्या है और उसका परिणाम क्या निकला? क्या उससे किसी समस्या का समाधान हुआ, संबंधित पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी या प्रभावित लोगों को राहत मिली? आयोजकों से उनके घोषित उद्देश्य, अपनाए गए तरीकों और प्राप्त परिणामों के बारे में प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक जागरूकता का हिस्सा है। ऐसा करना अपने आप में आंदोलन के अधिकार का विरोध नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और प्रभाव को समझने का प्रयास है। किसी की मंशा पर बिना प्रमाण आरोप लगाने से बचना भी उतना ही आवश्यक है।

नुकसान की भरपाई का प्रश्न भी गंभीरता से विचारणीय है। छोटे दुकानदार या दिहाड़ी मजदूर के पास इतना आर्थिक सहारा नहीं होता कि वह कई दिनों की कमाई खोने के बाद सहजता से अपना काम फिर शुरू कर सके। इसलिए जिन परिस्थितियों में कानून और न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत मुआवजे की जिम्मेदारी तय हो सकती है, वहाँ प्रभावित व्यक्ति को केवल नुकसान सहने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। साथ ही, आयोजनों की अनुमति देते समय प्रशासन को व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और आम नागरिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए।

लोकतंत्र केवल अपनी बात कहने की स्वतंत्रता का नाम नहीं है; यह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी है। जिस नागरिक को विरोध करने का अधिकार है, उसी नागरिक को निर्बाध आवागमन, सुरक्षित वातावरण और अपनी आजीविका चलाने का अधिकार भी है। इन अधिकारों को एक-दूसरे का विरोधी बनाने के बजाय उनके बीच संतुलन स्थापित करना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह शांतिपूर्ण विरोध के लिए उचित व्यवस्था बनाए, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और सामान्य जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का प्रयास करे।

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध केवल असहमति व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण अधिकार भी है। इस अधिकार की रक्षा करते हुए सामान्य नागरिकों की आजीविका और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। सरकार, प्रशासन, आंदोलन के आयोजकों और नागरिकों के बीच संवाद तथा सहयोग से ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है, जिसमें विरोध की आवाज भी सुनी जाए और किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों।

अंततः आंदोलन की सफलता केवल भीड़ के आकार, नारों की गूँज या समाचारों में मिली जगह से नहीं मापी जानी चाहिए। उसका मूल्यांकन इस बात से भी होना चाहिए कि उसने समस्या के समाधान में कितना योगदान दिया और आम नागरिक को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन उस आवाज के साथ जिम्मेदारी का स्वर भी सुनाई देना चाहिए। क्योंकि किसी भी आंदोलन में जनता का हित महत्वपूर्ण है और विरोध का अधिकार तथा रोज़ी-रोटी का अधिकार, दोनों एक साथ सुरक्षित रहने चाहिए।

विश्व राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सर्बिया: छोटा देश, बड़ा संदेश

देश छोटा है, किंतु संदेश बड़ा 56 वर्षीय राष्ट्रपति अलेक्सांद्र बुचिश के हाथों से अब सत्ता फिसल चुकी है। जनादेश ने छह फुट पांच इंच लंबे चश्मीश बुचिश का कद छांट दिया है। अब वह निवर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं। तय है कि उनकी करतूतों की जांच होगी, उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें और उनके सहयोगियों को सजा भी मिलेगी। जनादेश इतना स्पष्ट था कि उन्होंने सारे चुनाव परिणाम घोषित होने से पेशगी ही अपनी हार कुबूल कर ली। 250 सांसदों के सदन के नतीजों के ऐलान के अधबीच में ही बुचिश ने कहा – 'जाहिर है कि हमने यह चुनाव गँवा दिया है।'

देश छोटा है; चौतरफा अन्य देशों के भूखंडों से घिरा हुआ यानि भूआवेष्टित। आबादी तकरीबन पैंसठ लाख। इतिहास के थपेड़ों के बीच मानचित्र में उभरे इस योरोपीय राष्ट्र में युवकों ने कमाल कर दिखाया। चौदह सालों से जमे-जमाये कठोर और सुदृढ़ निजाम को उखाड़ फेंकना आसान न था, लेकिन छात्रों ने अपनी एकजुटता, संघर्षशीलता और आंदोलनधर्मिता से संसदीय चुनावों में सर्वथा नयी इबारतें लिखीं। फलतः स्टुडेंट्स-लिस्ट के उम्मीदवारों के लिये संसद में प्रवेश और सरकार के गठन के द्वार खुल गये। छात्रों की चुनौती अपनी जगह थी, लेकिन राजनीतिक पंडितों को यह यकीन न था कि छात्र समूहों द्वारा चुने हुये समाज के विभिन्न तबकों-अध्यापकों, डॉक्टरों, श्रमिकों और इंजीनियरों आदि के गैर पेशेवर उम्मीदवार वर्कर्स पार्टी के पेशेवर प्रत्याशियों को धूल चटा देंगे।

मगर ऐसा हुआ और डंके की चोट पर हुआ। सर्बिया में क्रांति बंदूक की नली से नहीं, वरन मतपेटियों से निकली। प्रतिरोध की जीत हुई और सत्ता की हार। यह कू-दे-ता नहीं था। निरंकुश, दमनकारी और भ्रष्ट सत्ता हारी और शांतिप्रिय, परिवर्तनकामी और अहिंसक सत्याग्रही जीते। यह भारत से हजारों मील दूर एक छोटे से योरोपीय राष्ट्र की परिघटना है। देश छोटा है, किंतु संदेश बड़ा 56 वर्षीय राष्ट्रपति अलेक्सांद्र बुचिश के हाथों से अब सत्ता फिसल चुकी है। जनादेश ने छह फुट पांच इंच लंबे चश्मीश बुचिश का कद छांट दिया है। अब वह निवर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं। तय है कि उनकी करतूतों की जांच होगी, उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें और उनके सहयोगियों को सजा भी मिलेगी। जनादेश इतना स्पष्ट था कि उन्होंने सारे चुनाव परिणाम घोषित होने से पेशगी ही अपनी हार कूबूल कर ली। 250 सांसदों के सदन के नतीजों के ऐलान के अधबीच में ही बुचिश ने कहा – 'जाहिर है कि हमने यह चुनाव गँवा दिया है।'

सर्बिया के साथ जातीय संघर्ष, नरसंहार और विनाश की दारूण-गाथा जुड़ी हुई है। यूगोस्लाविया के के विघटन के बाद बाल्कन क्षेत्र में विपदाओं की बाढ़ आ गयी। ऐसे में सन 2006 में सर्बिया स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में मानचित्र में उभरा और बीस सालों के गणतांत्रिक इतिहास में चौदह साल सत्ता की बागडोर बुचिश के हाथों में रही। दरअस्ल, बुचिश एक महत्वाकांक्षी, धूर्त और अनुदार राजनेता हैं। उन्होंने 23 वर्ष की वय में राजनीति में कदम धरे और अति उग्रवादी सर्बियन रेडिकल पार्टी ज्वाइन की। सन् 2008 में उन्होंने तोमिस्लाव निकोलस के साथ सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की। सन् 2012 से 2023 तक वह इसके अध्यक्ष रहे। सर्बियन रेडिकल पार्टी के सांसद की हैसियत से कानून में स्नातक बुचिश सन 1998 में सूचना मंत्री बने तो पूत के पांव पालने में दिख गये। वह 2000 में स्लोबोदान मिलोशेविक के पतन तक इस पद पर रहे और उन्होंने पत्रकारों पर कई दमनात्मक कानून थोपे और विदेशी टीवी चैनलों पर पाबंदी लगा दी। उनका दमन और उत्पीड़न का निरंकुश रवैया मुसलसल जारी रहा। सन् 2012 में वह उपप्रधानमंत्री बने और 2014 में पीएम। सन् 2017 और फिर 2022 में वह राष्ट्रपति चुने गये। इसी साल पीएम बनने के मकसद से उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव का दाँव खेला और स्टूडेंट लिस्ट के हाथों मुंह की खाई। बुचिश के पतन का कारण बनी एक नवंबर 2024 को नोवी साद रेलवे स्टेशन की दुर्घटना। कैनोपी गिरने से 16 लोगों की मौत के हादसे ने छात्रों को भड़का दिया। भ्रष्टाचार, नागरिक अधिकारों के हनन और संस्थानों के राजनीतिकरण के मुद्दों से आंदोलन को विस्तार और बल मिला। नवकुबेर मिरोस्लाव मिस्कोविच की पुत्र मार्को के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी, रिहाई और सरकार द्वारा हर्जाना देने के प्रसंग को अवाम ने स्वांग माना। बुचिश की घृणित मानसिकता का परिचय सेब्रेनिका कत्लेआम के बाद तब मिला, जब उन्होंने कहा - किल वन सर्ब, वी विल किल हंड्रेड मुस्लिम्स।' जाहिर है कि वह इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं और उनके भीतर एक कातिल विद्यमान है। दमन-उत्पीड़न के चलते उनके राजकाल में सर्बिया में भारी विदेशी निवेश, जीडीपी में वृद्धि और सफल विदेश नीति के दावों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने स्टूडेंट लिस्ट को भरपूर समर्थन दिया। यूं तो छात्रों का नेतृत्व किसी एक हाथ में नहीं था, अलबत्ता नोवी साद में मेडीसिन के प्रोफेसर एलिजा स्वदानोविच ने उन्हें बखूबी गाइड किया। बुचिश ने आंदोलनकारी छात्रों को 'ब्लाकेडर्स की संज्ञा दी, लेकिन नागरिकों के असंतोष और रोष की वाणी बनकर उभरे छात्र चुनाव में सर्ब अवाम की आंखों के तारे बनकर उभरे। छात्रों के नारे या सर्बिया, या माफिया, ज्ञान शक्ति है और सर्बिया हमारे साथ बढ़ रहा है, काम कर गये। अवाम ने निजाम बदलने के ध्वजवाहकों का साथ दिया। नतीजा सामने है। बेल्ग्रेड और सर्वत्र अपूर्व जश्न का माहौल। इतिहास से सबक नहीं लेने वाले बुचिश धराशायी हो गये। देखना दिलचस्प होगा कि संकटों के दौर से गुर रहे दुनिया के देश सर्बिया के सबक से क्या सबक लेते हैं?

समीक्षा

विजय जोशी

लेखक भेल भोपाल के पूर्व समूह महाप्रबंधक हैं।

भरत: अनासक्त कर्मयोग के आदर्श

कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात् हे प्राणी तू मात्र कर्म कर फल की आकांक्षा से रहित, क्योंकि फल की चाहत कर्म की पवित्रता को भंग कर देती है। कामनारहित कर्म उसे उसे एक नई ऊंचाई प्रदान कर देता है। यह कहा था कृष्ण ने द्वापर में पर भरत ने तो इसे एक युग पूर्व त्रेता में ही सिद्ध कर दिया था। यह शाश्वत सत्य खुलकर निखरा है एन.आई.टी. के. पूर्व प्रोफेसर डॉ. श्रीकृष्ण अग्रवाल की सद्य प्रकाशित पुस्तक 'भाई भरत' में। संक्षिप्त सार की एक बानगी।

त्रेता में भरत उस निर्गुण उपासना के प्रतीक हैं, जिसमें उनकी घनीभूत पीड़ा भक्ति का अवलंबन ले उसे समाज के समक्ष रचनात्मक स्वरूप प्रदान करती है, जिसे राम ने यूं बखान किया :

भरत अमित महिमा सुनु रानी
जानहिं रामु न सकहिं बखानी

राजनीति के संदर्भ में वे सुनीति के जीवंत स्वरूप हैं, न कि कूटनीति के। आज जहां लोग कानून की कमियां ढूंढकर अधर्म का सहारा लेते हैं वहीं भरत अपनी मां के अनर्थ का उत्तरदायित्व स्वयं पर वहन कर सच्चे हृदय से करते हैं पश्चाताप तथा प्रायश्चित।

सर्वप्रथम उनका नामकरण संस्कार ही कालांतर में उनकी पहचान बना :

बिस्व भरन पोषन कर जोई
ताकर नाम भरत अस होई

सोचिये तब राम भरत दोनों भ्राताओं का निर्मल निश्छल प्रेम कितना अद्भुत और अलौकिक रहा होगा :

राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे
तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे

भरत तक भ्रात प्रेम में इस तरह डूबे हुए थे कि कह उठे :

मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं
रसा रसातल जाइहि तबहीं

राम को लौटा लाने के प्रयास में सुमंत निषादराज आदि सबके आग्रह के बावजूद राम के कष्ट की अनुभूति सहेजे उन्हें स्मरण करते हुए वे पैदल ही चले :

रामु पयोदेहि पायँ सिधाए
हम कहँ रथ गज बाजि बनाए

अर्थात यह स्वयंसिद्ध है कि धर्म की आत्मानुभूति के साथ ही सेवा धर्म के भी प्रतीक हैं भरतः सबतें सेवक धरमु कठोरा।

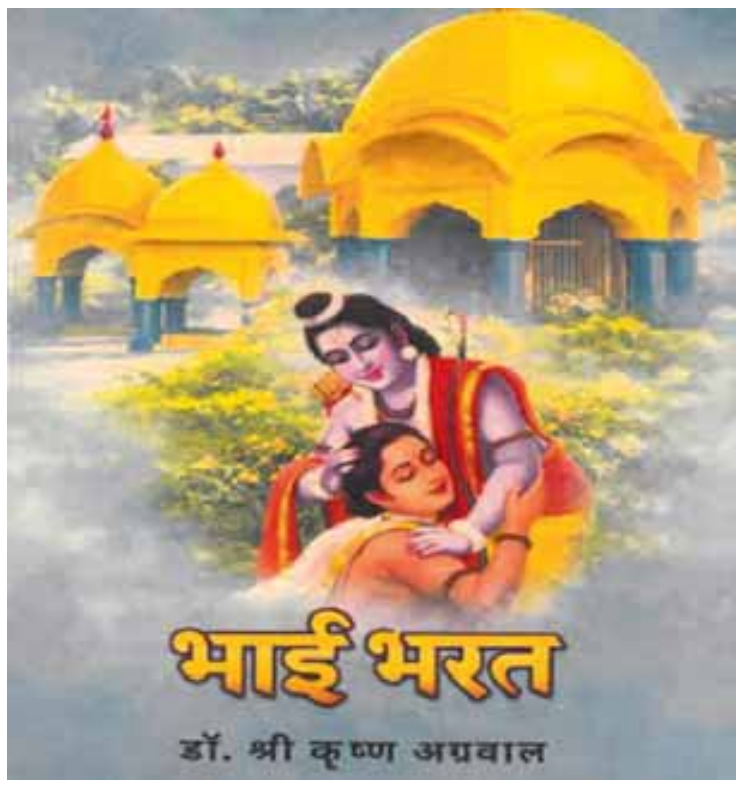

राम के अयोध्या के पुनारागमन का कोई नैतिक विकल्प ही दृष्टिगत ही नहीं था यानी पिता की आज्ञा का उल्लंघन एवं अवतार उद्देश्य की विफलता। तब भरत ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को स्वीकार किया और राम की चरण पादुका शिरोधार्य करते हुए राजसी वस्त्र त्याग नंदीग्राम में पर्णकुटी को स्थायी निवास बना शेष जीवन सहर्ष स्वीकार किया। इस धर्माचरण युक्त प्रसंग को लेखक ने कुछ यूं संग्रहित किया है :

- बड़ों की आज्ञा का अनुपालन
- अपराध स्वीकारोक्ति बजाय दूसरों पर थोपने के
- ध्येय की साधना में तन्मयता
- योग्यता के बावजूद दंभ से सर्वथा परे
- अन्य की पीड़ा की स्व में अनुभूति
- पादुका स्वीकार कर विवाद को समाधान से सुलझाया

कैकेयी प्रसंग : अगले प्रसंग में कैकेयी की अंतर्दशा की व्याख्या समाहित है, जिनका राम पर अगाध स्नेह था, किंतु अवतार उद्देश्य की पूर्णता हेतु उन्होंने अपमान की घनीभूत पीड़ा को सहकर भी सबसे दुष्कर कार्य का संपादन किया। यही कारण था कि राम चित्रकूट में सर्वप्रथम उन्हीं से मिले :

प्रथम राम भेंटी कैकेई
सरल सुभायँ भगति मति भेई

और इसी तर्ज पर लंका विजय पश्चात जब लौटे तो सबसे पहले कैकेयी निवास ही पहुंचे :

प्रभु जानी कैकई लजानी
प्रथम तासु गृह गए भवानी

रामकथा अद्भुत और अलौकिक है। कोई उच्च तकनीकी पायदान तक पहुंचा व्यक्ति इतनी गहराई से अनासक्त कर्मी भरत की संवेदनशीलता को कागज पर उकेर सके तो यह बात अपने आप में विलक्षण हो जाती है। यह करिश्मा किया है मेरे कॉलेज सहपाठी मित्र डॉ. अग्रवाल ने। सो वे बधाई के पात्र हैं। प्रकाशन एवं मुद्रण उत्तम। मुखपृष्ठ प्रभाव युक्त।

एक नोबेल और पुलित्ज़र का छोटा-सा ख्वाब है

'आजकल क्या लिख रहे हैं?' बोले, 'अपना परिचय। पिछला कुछ पुराना पड़ गया है।' पिछला परिचय मैंने पढ़ा था। उसमें वे संभावनाशील थे। नए में महत्वपूर्ण हो गए थे। रचनाएँ वही थीं; उनके आसपास विशेषणों की नई कॉलोनी बस गई थी। अब वे अपने समय के उन विरल रचनाकारों में थे जिनके बारे में यह बात मुख्यतः वे स्वयं जानते थे। परिचय के अंत में 'देश-विदेश में चर्चित' भी जुड़ गया था। विदेश में उनका भांजा रहता था। उसने एक बार फ़ोन पर पूछा था, 'मामाजी, किताब का क्या हुआ?' अंतरराष्ट्रीय चर्चा वहीं से शुरू हुई।

वक्रोक्ति

डॉ. लोकेन्द्र सिंह कोट
लेखक साहित्यकार हैं।

उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी सादगी से रहती थी। खादी पहनती, धीरे बोलती और अवसर मिलते ही सामने वाले की कुर्सी पर बैठ जाती। उन्होंने चाय का प्याला रखते हुए कहा, 'जीवन में बहुत कुछ नहीं चाहिए। बस, एक नोबेल और पुलित्ज़र का छोटा-सा ख्वाब है।' कहते हुए आँखें झुका लीं। इतनी विनम्रता के बाद कुछ देना बनता था। मैंने बिस्कुट बढ़ा दिया।

मैंने पूछा, 'आजकल क्या लिख रहे हैं?' बोले, 'अपना परिचय। पिछला कुछ पुराना पड़ गया है।' पिछला परिचय मैंने पढ़ा था। उसमें वे संभावनाशील थे। नए में महत्वपूर्ण हो गए थे। रचनाएँ वही थीं; उनके आसपास विशेषणों की नई कॉलोनी बस गई थी। अब वे अपने समय के उन विरल रचनाकारों में थे जिनके बारे में यह बात मुख्यतः वे स्वयं जानते थे। परिचय के अंत में 'देश-विदेश में चर्चित' भी जुड़ गया था। विदेश में उनका भांजा रहता था। उसने एक बार फ़ोन पर पूछा था, 'मामाजी, किताब का क्या हुआ?' अंतरराष्ट्रीय चर्चा वहीं से शुरू हुई।

उनका अध्ययन-कक्ष सुव्यवस्थित था। किताबों की जिल्दें कुर्ते से मेल खाती थीं और कुर्सी कैमरे की ओर खुलती थी। मैंने एक पुस्तक निकालनी चाही तो उन्होंने रोक दिया, 'पूरी पंक्ति बिगड़ जाएगी।' साहित्य के प्रति उनकी चिंता देखकर हाथ पीछे खींच लिया। दूसरों की पुस्तकें वे समर्पण-पृष्ठ तक ध्यान से पढ़ते थे। अपना नाम न मिले तो लेखक की स्मृति और सामाजिक प्रतिबद्धता, दोनों पर संदेह करते। अपनी किताब की बिक्री कम थी, लेकिन विमोचन की तस्वीरों में पर्याप्त भीड़ थी। प्रकाशक ने पाठकों की संख्या पूछी तो उन्होंने तस्वीरें भेज दीं। प्रकाशक ने दोबारा लिखा, 'पढ़ने वाले?' उन्हें यह व्यावसायिक दृष्टिकोण अशोभनीय लगा।

इन दिनों वे विश्वस्तरीय उपन्यास लिख रहे थे। उसमें एक गाँव था, जिसके सारे निवासी अपनी-अपनी तरह से पुरस्कार की संभावना बढ़ा रहे थे। किसान कर्ज़ में था, मज़दूर भूखा था, स्त्री पीड़ित थी। ज़मींदार भी परेशान था; इतने लोगों को दुखी रखने का ख़र्च लगातार बढ़ रहा था। मैंने पूछा, 'गाँव कब गए थे?' बोले, 'अब गाँव मेरे भीतर बसता है।' भीतर बसे गाँव की सुविधा थी कि उसके लोग पांडुलिपि पढ़कर आपत्ति नहीं कर सकते थे।

एक मज़दूर पात्र से उन्हें विशेष लगाव था। हर अध्याय में उसकी एक चीज़ चली जाती—पहले काम, फिर खेत, फिर पत्नी। बीसवें अध्याय तक उसके पास अंतरराष्ट्रीय करुणा के योग्य दुख बचा था। एक जगह उसने मज़दूरी बढ़ाने की माँग की तो लेखक ने वाक्य काट दिया। बोले, 'यह पात्र की भाषा नहीं है।' संशोधित प्रति में मज़दूर चुपचाप आकाश देख रहा था। उनके उपन्यास में ग़रीब अक्सर आकाश देखते थे; नीचे देखने से हिसाब दिखाई देने लगता था।

पांडुलिपि तीन आलोचकों को भेजी गई। पहले ने भाषा सँवारने को कहा, दूसरे ने कथानक। तीसरे ने लिखा, 'यह हमारे समय की अंतरात्मा में एक बेचैन हस्तक्षेप है।' तीसरे को भोजन पर बुलाया गया। अंतरात्मा के साथ पनीर टिक्का परोसा गया। लौटते समय आलोचक अपनी नई पुस्तक दे गए। अगले सप्ताह उन्होंने उस पर लिखा, 'हिंदी आलोचना में ऐसा निर्भीक स्वर दुर्लभ है।' साहित्य में संवाद की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित हुई।

अब अनुवाद आवश्यक था। उन्होंने अनुवादक से कहा, 'स्थानीयता बची रहे, लेकिन विदेशी पाठक असुविधा महसूस न करे।' अनुवादक ने एक वाक्य का अर्थ पूछा तो वे कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, 'लेखक सब बता दे तो पाठक क्या करेगा?' अनुवादक ने उस दिन से अग्रिम भुगतान लेना शुरू कर दिया। कठिन अंशों को लेकर दोनों में समझौता हो गया था—लेखक उन्हें शिल्प कहते, अनुवादक अलग से शुल्क जोड़ देता।

उनकी दिनचर्या कठिन थी। सुबह वरिष्ठ लेखकों के स्वास्थ्य की चिंता, दोपहर संपादकों की व्यस्तता का सम्मान, शाम संभावित निर्णायकों की निष्पक्षता की प्रशंसा। रात तक उँगलियाँ थक जातीं। फिर भी उन्हें शिकायत थी कि साहित्य में संबंधों से काम होता है। मैंने प्रमाण पूछा। बोले, 'जिनसे संबंध नहीं बनाए, उन्हीं को मिल गया।'

किसी ने बताया कि साहित्य के नोबेल में स्वयं अपना नाम प्रस्तावित नहीं कर सकते और नामांकन की जानकारी पचास वर्ष गोपनीय रहती है। वे देर तक विचार करते रहे। अगले दिन परिचय में 'नोबेल के संभावित दावेदार' जुड़ गया। मैंने आधार पूछा तो होंठों पर उँगली रख दी। पुलित्ज़र की अमेरिकी नागरिकता अथवा निवास संबंधी पात्रता सुनकर अलबत्ता विचलित हुए। बोले, 'प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती।' मैंने कहा, 'फ़ॉर्म में पता भी भरना पड़ता है।'

कल मिले तो उदास थे। बेटे ने उनका उपन्यास पढ़ लिया था। पूछ रहा था, 'तीसरे अध्याय में जो औरत कुएँ में कूदी, वह सातवें में चाय कैसे बना रही है?' उन्होंने समझाया, 'वह स्त्री की जिजीविषा है।' बेटे ने दोनों पृष्ठ खोल दिए। तब से किताब उसके कमरे से हटा दी गई है।

पुरस्कारों के लिए अलमारी में जगह अब भी खाली है। उसमें पत्नी ने बिजली का बिल रख दिया है। उसकी अंतिम तिथि गोपनीय नहीं है।

अचानक भोपाल पहुंचे भागवत, जैन मुनि से की मुलाकात

समिधा में संघ के अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, इंदौर रवाना

भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत बुधवार सुबह अचानक भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने संघ कार्यालय समिधा में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद एमपी नगर के पास चातुर्मास कर रहे जैन मुनि समय सागर महाराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भागवत इंदौर के लिए रवाना हो गए। वे वहां संघ के शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर आयोजित 'चरैवेति-एकत्रीकरण' कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल पहुंचने पर संघ प्रमुख का स्वागत स्वप्निल कुलकर्णी, संघ के प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता और कैलाश लोवंशी ने किया। भागवत का भोपाल प्रवास ऐसे समय हुआ, जब इंदौर में संघ के शताब्दी वर्ष के समापन का बड़ा आयोजन है। भोपाल प्रवास के दौरान भागवत संघ कार्यालय समिधा पहुंचे। यहां उन्होंने संघ के अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद दोपहर पौने 3 बजे से शाम साढ़े 4 बजे के बीच जैन मुनि समय सागर महाराज से मुलाकात का कार्यक्रम था। मुलाकात के बाद वे इंदौर रवाना हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर का 'चरैवेति-एकत्रीकरण' इसी श्रृंखला का समापन कार्यक्रम है।

केंद्र के समान महंगाई राहत देने की मांग

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को लिए गए निर्णय के अनुरुप कुल 5% पुनरीक्षित दरों से मंहगाई राहत के भुगतान आदेश को संदर्भित करते हुए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं वित्त के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 01 जनवरी 2026 से 2% एवं 01 जुलाई 2026 से 3% (कुल 5%) मंहगाई राहत के शीघ्र भुगतान आदेश जारी करने की मांग की है।

एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने कहा कि 01 जनवरी 2026 से 2% एवं 01 जुलाई 2026 से 3% (कुल 5%) मंहगाई राहत के शीघ्र भुगतान आदेश जारी कर समस्त एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। एसोसिएशन के भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने आशा व्यक्त की कि सरकार वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों की आर्थिक कठिनाइयों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे उन्हें बढ़ती मंहगाई से राहत मिल सके ।

दिल्ली में गुर्जर समाज की स्वाभिमान रैली में प्रदेश के बंधुओं की सहभागिता, सोहागपुर के बंधुवर शामिल

सोहागपुर निप्र। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वावधान में गुर्जर समाज की स्वाभिमान रैली तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में देश के समस्त प्रान्तों के प्रतिनिधियों, सामाजिक, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्यमंत्री अतिथि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल थे। इस अखिल भारतीय गुर्जर समाज के गरिमामय कार्यक्रम में सोहागपुर सेमरी हरचंद अखिल भारतीय गुर्जर समाज जिलाध्यक्ष एवं कृषि उपज मंडी पूर्व अध्यक्ष राजा भैया पटेल ने वहां पहुंच कर अपनी सहभागिता निभाई। श्री राजा भैया पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी शामिल हुए।

मध्यप्रदेश की दमदार उपस्थिति- जिसमें प्रदेश सरकार में मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक रामकिशोर दोगने, विधायक साहब सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक रामबरन सिंह गुर्जर, देवेंद्र सिंह पटेल युवा प्रदेश अध्यक्ष सोनू पहलवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता हाकम सिंह गुर्जर, होतम सिंह गुर्जर, गजेंद्र कंसाना, पंजाब सिंह गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य दौलत राम पटेल, ऋतुराज, राजेश पटेल, कमलेश चौधरी, पत्रकार जगदीश पटेल गुर्जर और दयाल सिंह गुर्जर सहित सैकड़ों प्रतिनिधियों ने रैली में समाज की एकजुटता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया। श्री पटेल ने दिल्ली से आकर इस प्रतिनिधि को बताया कि आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में गुर्जर समाज ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों से आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई गई। रैली में समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और विभिन्न पिछड़ी जातियों को एक मंच पर लाने पर जोर दिया गया। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गुर्जर महासभा ने गुर्जर समाज के साथ कुर्मी, पाटीदार सहित अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों को एकजुट करने की पहल की गई।

शरदोत्सव समिति संयोजक ने आभार व्यक्त जताया

सोहागपुर निप्र। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शारदोत्सव समिति संयोजक पवनसिंह चौहान एवं शरदोत्सव समिति अध्यक्ष नारायण रघुवंशी ने कार्यक्रम में विगत वर्षो से कार्यक्रम में सहयोग करने पर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस बुन्देली लोकगीत गायक जित्तू खरे बादल बुंदेलखंडी एवं राई नृत्य का आयोजन सांदीपनि विधालय परिसर में आयोजित किया गया था। आपने शरदोत्सव समिति के सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया है।

माखननगर मां नर्मदा सूरजकुंड के पास परशुराम भवन निर्माण का भूमिपूजन पूर्व गृहमंत्री पंडित नरोत्तम मिश्रा ने किया

सोहागपुर निप्र। सोहागपुर विधानसभा के माखन नगर के समीपवर्ती मां नर्मदा नदी घाट सूरजकुंड में पटे घाट पर भगवान परशुराम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन संपन्न विगत दिवस मध्यप्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट गृहमंत्री माननीय पं. नरोत्तम मिश्रा जी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पंडित बृज बिहारी सरकार, नीलवड़ आश्रम भोपाल एवं गृहस्थ साधक पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल जी महाराज श्री शम्भू दरबार सोहागपुर थे इस अवसर अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित करके मां नर्मदा का अभिषेक एवं भूमि पूजन संपन्न किया गया।

इसी अवसर पर पंडित गौरव व्यास एवं अन्य विद्वान पंडितों द्वारा उच्च स्वर में वैदिक मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए देवोक्त पद्धति से विधि-विधानपूर्वक पूजन कराया । इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के साधु-संतों के साथ सामाजिक एवं गणमान्य नागरिक मनमोहन बावरिया, रमन शुक्ला, पत्रकार आदेश शर्मा, चुन्नीलाल मुद्गल, हर्षित गुरु, भाजपा कार्यकर्ता सहित स्थानीय समाजसेवी एवं श्रद्धालु

बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके पूर्व कार्यक्रम के आयोजक पंडित महेन्द्र तिवारी ने आमंत्रित अतिथियों का माल्यार्पण करके शॉल, श्रीफल भेंट करते हुए स्वागत एवं सम्मान किया। श्री शंभू दरबार के पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल ने बताया कि इस धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के माध्यम से माँ नर्मदा घाट के विकास तथा भगवान परशुराम मंदिर निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिससे भगवान् परशुराम जी के प्रति आस्था का केन्द्र बनेगा।

'कभी ताल है जिंदगी तो कभी चौपाल है जिंदगी'

भोपाल। राजधानी भोपाल में पत्रकारों की कालोनी अभिव्यक्ति नगर में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 'शरदोत्सवः एक काव्यमयी संध्या' का आयोजन हुआ। सुरभ्र चांदनी रात्रि में वरिष्ठ गीतकार डॉ. रामवल्लभ आचार्य, शंकर दीक्षित, गजलकार डॉ. प्रार्थना पंडित, दोहाकार मनीष बादल, व्यंग्यकार राजेंद्र गट्टानी, सुनील चतुर्वेदी, नई कविता के कवि पत्रकार दीपक पगारे और सतीश एलिया ने श्रोताओं को काव्य रस से आनंदित भी किया और आज के समय की विसंगतियों पर विचार के लिये विवश किया।

डॉ. आचार्य ने रचना सुनाई-कभी शैल शिखर सी तो कभी ताल जिंदगी, कभी तंग गली तो कभी चौपाल जिंदगी, ऊपर से शांत किन्तु है भीतर उथल पुथल, बस यूँ समझ लो जैसे है भोपाल जिंदगी।

डॉ. प्रार्थना प्रार्थना पंडित ने तरन्नुम में ये गजल सुनाई तो श्रोता लय के साथ तालियों की ताल देकर झूम उठे-

प्यार फ़ोन पर जतलाता है
शिकवे मिल कर करता है
कैसा पागल लड़का है वो
बेकल बेकल फिरता है

मुझको टेक्स्ट नहीं करता है चाहे कितने दिन बीते
झूठी उसकी शान की ख़ातिर कितने मौसम हों रीते
आंसू मेरे देख ना पाए खो देने से डरता है
कैसा पागल...

व्यंग्यकार सुनील चतुर्वेदी ने इस रचना से खूब दाद बटोरी-

तू गीत लिखेगा न ग़ज़लकार बनेगा,
व्यंग्यकार की औलाद है व्यंग्यकार बनेगा ।
अच्छा है तुझे छन्द का कुछ ज्ञान नहीं है,
लय का और ताल का भी भान नहीं है ।
ये छंद तेरे भेजे में घुस भी न सकेगा,
अच्छा है तेरा इसकी तरफ़ ध्यान नहीं है ।

पत्रकार कवि दीपक पगारे ने रचना सुनाई-

एक अभिशप्त पीढ़ी का दर्द झेल रही चांदनी की पीड़ा का अहसास किसी को नहीं। अपने दूधिया आँचल में सारी वेदना छिपाए भटक रही है जंगल जंगल।

मंच संचालन कर रहे दोहाकार मनीष बादल ने यह दोहे सुनाकर अभिभूत किया-

तन को दस-दस रोग दे, मन में करती शोर।
'बादल' कहता है तभी, चिंता आदमख़ोर।।

नवगीतकार मनोज जैन 'मधुर 'ने अपने रचना पाठ से शरदोत्सव को नई ऊंचाई दी।

लय में रहना सीख बावरे ,
लय से दूर न जा।

सात रंग की लय में होता
इंद्रधनुष सतरंगा।
लय में घूम रही है धरती
लय में बहती गंगा।

कवि राजेंद्र गट्टानी की रचनाओं को भी खूब सराहा गया।

वरिष्ठ गीतकार ने शंकर दीक्षित अपने गीतों से श्रोताओ को मंत्रमुग्ध किया। बानगी देखिए- अंगुली पकड़ चलाया कभी हाथ थाम कर

पांव से ज़मी पै नजर आसमान पर
मां बाप की दुआओं का असर तो देखिए-
पहुंचा दिया गरीब को जय के मुकाम पर।

अभिव्यक्ति सोसायटी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कवियों का अभिनंदन किया। शरदोत्सव के आरंभ में नन्ही भरतनाट्यम नृत्यांगना शताक्षी एलिया ने पुष्पांजलि और भैरवी की मनमोहक प्रस्तुति से दर्शको को मंत्रमुग्ध कर दिया। शरदोत्सव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

सांची की बोधि परंपरा गुजरात पहुंची, श्रीलंका से पवित्र पौधा लेकर पहुंचे वानगल उपतिस्स नायक थेरो

गांधीनगर के शून्यता ध्यान केंद्र में होगा बोधि पौधे का रोपण, 16 एकड़ में विकसित होगा आध्यात्मिक परिसर

रायसेन। भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान, करुणा और शांति के संदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में सांची की ऐतिहासिक बौद्ध परंपरा गुजरात पहुंची है। श्रीलंका के अनुराधापुरा से पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा लेकर महाबोधि सोसायटी ऑफ श्रीलंका एवं सांची के अध्यक्ष वानगल उपतिस्स नायक थेरो गांधीनगर पहुंचे। यहां शून्यता ध्यान केंद्र के उद्घाटन समारोह में पौधे को केंद्र की संस्थापक तेजल चुडासमा और गुजरात पुलिस के पूर्व एडीजी अभय चुडासमा को सौंपा । इस पवित्र पौधे का रोपण ध्यान केंद्र परिसर में किया जाएगा। बोधि वृक्ष से जुड़ी सांची की ऐतिहासिक विरासत और बौद्ध परंपरा की प्रेरणा से गुजरात में की जा रही यह पहल शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक साधना के प्रसार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समारोह में मुंबई स्थित मेनलाई जामत्से तिब्बती बौद्ध केंद्र के संस्थापक वेन. गेशे लोबसांग तेनज़िन, बेंगलुरु के वेन. धापका त्रितुल रिम्पोछे, माउंट आबू स्थित नीम करौली बाबा आश्रम के स्वामी

गोविंद महाराज, जापान के रेवरेंड वाई. पन्नारामा तथा सांची स्थित चेतियागिरी विहार के तपस्सी भंते प्रमुख रूप से शामिल रहे।

16 एकड़ में विकसित होगा शून्यता ध्यान केंद्र- शून्यता ध्यान केंद्र की संस्थापक तेजल चुडासमा ने केंद्र की परिकल्पना और उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि आधुनिक जीवनशैली की व्यस्तता के बीच लोगों को आंतरिक शांति और मानसिक सुकून की आवश्यकता महसूस हो रही है। केंद्र का उद्देश्य ध्यान साधना के माध्यम से लोगों को मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और सकारात्मकता का अनुभव करने का अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि लगभग 16 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस केंद्र में करीब पांच हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां निर्धारित अनुशासन का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन और आवास उपलब्ध कराने की भी योजना है। इस तरह केंद्र में आध्यात्मिक साधना के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दिया जाएगा।

'अग्रश्रावक' पुस्तक का विमोचन, बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के जीवन पर प्रकाश - समारोह का एक अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण भगवान गौतम बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत्त और महामोग्गलाना के जीवन, साधना एवं योगदान पर आधारित पुस्तक 'अग्रश्रावक' का विमोचन रहा। पुस्तक के लेखक शकील अहमद सिद्दीकी महाबोधि सोसायटी ऑफ सांची के कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने पुस्तक में भगवान बुद्ध के इन दोनों अग्रणी शिष्यों के जीवन और धम्म के प्रति उनके समर्पण को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

कन्या शाला में न्यायिक मजिस्ट्रेट तेजसिंह सासन ने विधिक साक्षरता शिविर में सारगर्भित उद्बोधन दिया

सोहागपुर निप्र। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश नर्मदापुरम के आदेश अनुसार एवं श्री अतुल सक्सेना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार समीपवर्ती ग्राम अकोला तहसील सोहागपुर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री तेजसिंह सासन के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री तेज दीप सिंह सासन ने छात्राओं को विधिक कानून की सारगर्भित जानकारी देकर समझाईश दी। वहीं आपने छात्राओं को गुड टच (सुरक्षित स्पर्श) एवं बेड टच (असुरक्षित स्पर्श) के बारे में विस्तार से बताकर समझाईश दी। इस अवसर पर छात्राओं के अलावा शिक्षक, शिक्षिकाओं, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सीईसी सदस्य श्री सुनील लिमाये ने दिए निर्देश

चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन रोकने तीनों राज्यों के अधिकारी मिलकर करें प्रभावी कार्रवाई

16 वन चौकियां स्थापित होंगी, सप्ताह में दो बार संयुक्त जांच और हर तीन माह में अंतरराज्यीय बैठक; कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से होगी निगरानी

मुरैना (निप्र)। चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के संबंधित जिलों के अधिकारी आपसी समन्वय से संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) के सदस्य श्री सुनील लिमाये ने मंगलवार को देवरी में आयोजित अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीनों राज्यों के पुलिस, वन, खनिज, परिवहन एवं राजस्व विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करें। उन्होंने निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 16 वन चौकियां स्थापित करने, चंबल नदी क्षेत्र में कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से निगरानी करने तथा नियमित संयुक्त जांच करने पर जोर दिया। साथ ही, अवैध उत्खनन से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों का परस्पर आदान-प्रदान करने और प्रत्येक तीन माह में अंतरराज्यीय बैठक आयोजित कर कार्रवाई की समीक्षा करने के निर्देश दिए। श्री लिमाये ने कहा कि चंबल नदी के प्राकृतिक स्वरूप एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अवैध रेत उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। इसके लिए तीनों राज्यों के संबंधित विभाग नियमित संयुक्त जांच करें तथा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित सूचनाओं और आंकड़ों का परस्पर आदान-प्रदान करें। प्रत्येक तीन माह में आयोजित होने वाली अंतरराज्यीय बैठक में की गई कार्रवाई, निगरानी व्यवस्था और अवैध गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ग्वालियर के मुख्य वन संरक्षक श्री लोवित भारती, कलेक्टर मुरैना श्री लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर भिण्ड श्री पवन जैन, श्योपुर कलेक्टर के प्रतिनिधि,कलेक्टर धौलपुर श्री बी.टी. श्रीनिधि, भरतपुर के मुख्य वन संरक्षक श्री पी. कथिरवेल,पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मीणा, पुलिस अधीक्षक भिण्ड श्री सूरज वर्मा, पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान, वन मंडलाधिकारी मुरैना श्री हरिशचन्द्र बघेल तथा आगरा ईस्ट के पुलिस उपायुक्त श्री अभिषेक अग्रवाल सहित मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, धौलपुर एवं आगरा के खनिज विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 16 वन चौकियां स्थापित कर अवैध गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर श्री लिमाये ने निर्देश दिए कि चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर निगरानी के लिए मुरैना वन मंडल द्वारा 16 वन चौकियां स्थापित की जाएं। मैदानी अमले को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर कार्रवाई प्रभावी बनाई जाए। वन विभाग को अतिरिक्त अमला उपलब्ध कराने के साथ आवश्यक हथियार भी दिए गए हैं, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके। कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से होगी निगरानी चंबल नदी क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चंबल नदी के पुल पर आगामी 15 दिनों में पीटीजेड कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर के माध्यम से भी निगरानी की व्यवस्था विकसित की जाएगी। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त वाहनों को नियमानुसार राजसात करने के निर्देश दिए गए। सप्ताह में दो बार संयुक्त जांच, अनुविभागीय अधिकारी माह में दो बार करेंगे निरीक्षण अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तहसीलदार, वन परिक्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी एवं खनिज निरीक्षक अनुभागवार सप्ताह में दो बार संयुक्त भ्रमण कर जांच करेंगे। जांच के दौरान अवैध उत्खनन, रेत परिवहन एवं संदिग्ध वाहनों की गतिविधियों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुविभाग स्तर के अधिकारी प्रत्येक माह दो बार निरीक्षण कर कार्रवाई की समीक्षा करेंगे, ताकि निगरानी व्यवस्था नियमित बनी रहे और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो।

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में ए. पी. सी. की समीक्षा बैठक आयोजित

अशोक नगर (निप्र)। सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के. सी. गुप्ता की अध्यक्षता में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के कमिश्नर,कलेक्टर एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ए. पी. सी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों के लिए पानी, बीज एवं खाद की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से जिले में कृषि कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण बीजों की व्यवस्था तथा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिये। एपीसी श्री के सी गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को कृषि कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पानी, बीज एवं खाद की उपलब्धता बनाए रखने तथा इनकी आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। नरवाई में आग लगाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए हों आवश्यक उपाय नरवाई में आग लगाने की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। किसानों को नरवाई में आग लगाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने तथा फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। साथ ही संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उद्यानिकी खाद्य प्रसंकरण,सहकारिता तथा संबद्ध संस्थाएं पशुपालन एवं डेयरी विकास,मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की विस्तार से कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर निर्देश दिये गए। जिला स्तर पर एनआईसी कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेश जैन, अपर कलेक्टर श्री डी एन सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री विकास कुमार आनंद, उप संचालक कृषि श्री अमित सिंह भदोरिया एवं संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने जनसुनवाई में सुनीं आमजन की समस्याएं

चार जरूरतमंदों को रेडक्रॉस से 32 हजार की आर्थिक सहायता

शिवपुरी (निप्र)। जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने आज सैकड़ों आवेदकों की समस्याओं और शिकायतों को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही त्वरित निराकरण किया, वहीं शेष आवेदनों के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए चार जरूरतमंदों को रेडक्रॉस मद से कुल

32 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर चेक प्रदान किए। इसमें ग्राम देदखुर्द बछौरा (पोहरी) निवासी महिला लक्ष्मी सेन को 10 हजार रुपए, ग्राम रेहरगवां बधोरा (करैरा) के दिव्यांग युवक सुमित कुमार वंशकार को इलाज हेतु 10 हजार रुपए तथा कमलागंज शिवपुरी निवासी गंभीर बीमारी से ग्रसित जितेंद्र धानुक को इलाज में मदद के लिए 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, ग्राम ख्यावदा (नरवर) निवासी गजराज सिंह को 2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर चेक सौंपा गया।इसके अलावा सहकारी बैंक में जमा राशि की मांग लेकर भी कई आवेदक आए तब कलेक्टर श्री वर्मा ने सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बकायेदारों से सख्ती से राशि की वसूली की जाए और हितग्राहियों की राशि दी जाए।कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज से आने वाले आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आवेदनों के निराकरण में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए।

जन सुनवाई के दौरान सुनी आधा सैकड़ा से अधिक आवेदकों की समस्याएं

दतिया (निप्र)। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। आयोजित जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए आधा सैकड़ा आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान सीईओ जिला जिला पंचायत श्री शौलेन्द्र सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

मातृत्व और कर्तव्यनिष्ठा की अनूठी मिसाल

पटवारी श्रीमती संध्या शर्मा का मातृत्व और शासकीय दायित्व निर्वहन में संतुलन

शिवपुरी (निप्र)। आज के दौर में महिलाएं घर और बाहर दोनों मोर्चों पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं शिवपुरी जिले के पटवारी हल्का डोंगर (क्रमांक 122) में पदस्थ श्रीमती संध्या शर्मा। वह एक तरफ जहाँ शासन की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना पंजीयन कार्य के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मात्र दो वर्ष के अपने छोटे से बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं।एक तरफ जहाँ बच्चे की देखभाल वहीं दूसरी तरफ शासकीय स्वामित्व योजना के अंतर्गत जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करना और पंजीयन जैसे तकनीकी व जिम्मेदारी भरे कार्य समय पर पूरे करने होते हैं। श्रीमती संध्या शर्मा अपने दो साल के बच्चे को साथ लेकर अपने क्षेत्र में ड्यूटी पर पहुँचती हैं। उनके पति भी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, जिससे पारिवारिक व्यस्तताएं और बढ़ जाती हैं, परंतु इसके बावजूद वे कार्य के प्रति गंभीर हैं ।श्रीमती संध्या शर्मा अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर क्षेत्र में पहुंचती हैं तथा स्वामित्व योजना से संबंधित भूमि अभिलेख तैयार करने और पंजीयन संबंधी कार्यों का निर्वहन करती हैं। उनके पति भी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक एवं शासकीय दायित्वों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपने कार्य के प्रति गंभीर हैं।उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार स्वामित्व योजना के तहत जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में स्वामित्व पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में राजस्व विभाग के मैदानी स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अभिलेखों का संधारण, आवश्यक जानकारी का संकलन और पंजीयन संबंधी प्रक्रियाओं का संपादन किया जा रहा है।

ग्वालियर व्यापार मेला के लिए 2,090 दुकानें आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध

अब तक 644 आवेदन प्राप्त

ग्वालियर (निप्र)। ग्वालियर व्यापार मेला का आयोजन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जा रहा है। मेला प्राधिकरण द्वारा 2,090 दुकानों को आरक्षित श्रेणी में शामिल कर आवंटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इन दुकानों के लिए अब तक कुल 644 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। दुकान आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में ऑटोमोबाइल्स, झूला, इलेक्ट्रॉनिक्स, पक्की दुकानें, कोठरी, चबूतरा, सी की दुकानें, रेलवे ट्रैक की दुकानें, डीएनएसटी, एसटी, एक्सपो और एएम की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों का आवंटन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त 644 आवेदनों के माध्यम से मेला प्राधिकरण को लगभग 80 लाख रुपये किराये के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए ऑनलाइन माध्यम से 9.35 लाख रुपये की राशि भी प्राधिकरण को प्राप्त हुई है।

एसडीएम द्वारा कृषि उपज मंडी श्योपुर का निरीक्षण

अनुपस्थित 9 कर्मचारियों के विरूद्ध वेतन काटने के निर्देश

श्योपुर (निप्र)। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में एसडीएम एवं भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी श्योपुर श्री गगन सिंह मीना द्वारा श्योपुर कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडी में कर्मचारियों की उपस्थिति, साफ-सफाई, किसानों के लिए छाया एवं नीलामी व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के संबंध में नियमानुसार एक दिवस का वेतन राजसात करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये कर्मचारी श्यामा शर्मा, सीमा कौशल, महेन्द्र सिंह, अमित धूलिया, दुष्यंत वर्मा, सुनील धूलिया, अनिल दौहरे का एक-एक दिन का तथा कीर्ति कस्तवार और रफीक अली का आधे-आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश मंडी सेकेट्री को दिये गये। साथ ही मंडी परिसर में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। भारसाधक अधिकारी एवं एसडीएम श्री मीना ने मंडी प्रबंधन को निर्देशित किया कि मंडी में उपज विक्रय के लिए आने वाले किसानों के बैठने एवं विश्राम हेतु पर्याप्त छाया की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त कृषि उपज की नीलामी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को अपनी उपज के विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडी परिसर में व्यवस्थाओं को नियमित रूप से बनाए रखने तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर करीला में समरसता सम्मेलन आयोजित

जनजाति आयोग के सदस्य श्री बारेलाल अहिरवार ने की सहभागिता, सामाजिक समरसता और एकता का दिया संदेश

अशोक नगर (निप्र)। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के पावन अवसर पर अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करीला में सोमवार को समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जनजाति आयोग के सदस्य श्री बारेलाल अहिरवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया तथा महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन, उनके आदर्शों और समाज को दिए गए अमूल्य योगदान को स्मरण किया। श्री अहिरवार ने कहा कि आज हमारे संपूर्ण भारत वर्ष में महर्षि बाल्मीकि जयंती आयोजित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि समरसता सम्मेलन का उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारे, समानता और एकता की भावना को मजबूत करना रहा। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उनके आदर्श समाज को सत्य, सदाचार, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु युवाओं को स्वरोजगार जोडे

जाने के लिये जागरूक करना होगा। कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि के रूप में मुंगावली विधायक श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी महान रचना रामायण के माध्यम से भारतीय संस्कृति, नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाया। उनका जीवन और कृतित्व समाज को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनकी जयंती पर आयोजित इस प्रकार के सम्मेलन सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर महंत श्री नारायण दास जी,सपना नहारिया,नरेश बालू,जितेन्द्र नहारिया,प्रकाश नहारिया,रवि मोहने, सहित समाजसेवी, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

बेटा मम्मी-मम्मी पुकारता रहा, चौथी मंजिल से कूद गई मां

मुरैना में नीचे खड़े परिजन समझाते रहे; गंभीर हालत में ग्वालियर फिर दिल्ली रेफर

मुरैना, निप्र। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल महिला को मुरैना जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे ग्वालियर और फिर दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली में उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना नैनागढ़ रोड की सोमवार तड़के की है। वीडियो आज सामने आया है।

वीडियो में महिला घर की चौथी मंजिल की बालकनी से कूदती दिखाई दे रही है। नीचे खड़े परिवार और मोहल्ले के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं रुकी। वीडियो में एक बच्चा महिला को 'मम्मी-मम्मी' पुकारता सुनाई दे रहा है।

एक महीने पहले किराए पर आया था परिवार

सीएसपी कवीन्द्र सिंह चौहान के अनुसार मुरैना के नैनागढ़ रोड पर रहने वाला एक दंपति मूल रूप से अंबाह का निवासी है। परिवार करीब एक महीने पहले रामहेत सिकरवार के मकान में किराए पर रहने आया था। घर का सामान भी अभी ठीक से व्यवस्थित नहीं हुआ था। परिवार ने यहां दूध डेयरी की दुकान भी खोली थी।

30 मिनट तक महिला को समझाते रहे परिजन

सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे महिला मकान की छत पर पहुंच गई। डेयरी का काम होने के कारण पति और आसपास के कुछ लोग पहले से जाग रहे थे। उस समय मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी निकल रहे थे। महिला को छत पर देखकर पति और बच्चे ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाया। शोर सुनकर आसपास की महिलाएं भी अपनी छतों पर आ गईं। सभी ने करीब 30 मिनट तक महिला को समझाने और शांत करने की कोशिश की।

महिला नहीं मानी और अचानक छत से कूदी

करीब 30 मिनट तक समझाने के बावजूद महिला नहीं मानी और अचानक छत से छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पहले मुरैना जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस पता लगा रही है कि महिला ने किन परिस्थितियों में जान देने की कोशिश की।

किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है एमपी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले-प्रकृति एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कार्य जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण और प्रकृति एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों, विशेषकर कृष्णमृग एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा

- **हेलीकॉप्टर से रंथभंवर में कृष्णमृग-नीलगाय रेस्क्यू अभियान का किया अवलोकन**
- **दक्षिण एशिया में अपनी तरह का यह पहला प्रयास शाजापुर जिले में हो रहा है साकार**

सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शाजापुर जिले में किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष बोमा पद्धति से कृष्णमृग और नीलगाय के रेस्क्यू का अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में दक्षिण अफ्रीका की विशेष टीम की सहायता से वन्यजीवों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर निर्धारित सुरक्षित वन क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रेस्क्यू के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि वन्यजीवों को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज शाजापुर जिले के ग्राम रंथभंवर पहुंचकर कृष्णमृगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए संचालित प्रोजेक्ट एन्टीलोप ट्रांसलोकेशन अन्तर्गत किए जा रहे रेस्क्यू अभियान के द्वितीय चरण का अवलोकन किया। उल्लेखनीय हैं कि उक्त अभियान शाजापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है। इसके तहत द्वितीय चरण में 2000 कृष्णमृगों के स्थानांतरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि अब तक शाजापुर जिले से लगभग 1236 से अधिक कृष्णमृगों और नीलगायों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू किए गए कृष्णमृगों को श्योपुर के जंगलों, गांधी सागर और रानी दुर्गावती रिजर्व फॉरेस्ट सहित निर्धारित वन क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए 11 ट्रकों की व्यवस्था की गई है। वन्यजीवों के सुरक्षित परिवहन के लिए पशु चिकित्सकों, आवश्यक उपकरणों तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला रेस्क्यू अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हेलीकॉप्टर की सहायता से बोमा पद्धति पर आधारित वन्यजीव रेस्क्यू का यह अभियान दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है। इस पहल से वन्यजीवों का संरक्षण करने के साथ किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने अभियान में जुटे वन विभाग एवं प्रशासन की टीम के प्रयासों की सराहना भी की तथा विश्वास व्यक्त किया कि इस परियोजना की सफलता से देश के अन्य राज्यों को भी ऐसी पहल करने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अभियान की प्रगति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कैमोफ्लाज्ड मचान से बोमा पद्धति के माध्यम से किए जा रहे कृष्णमृग एवं नीलगाय के रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन विभाग एवं प्रशासनिक टीम के साथ समूह छायाचित्र भी खिंचवाया। इस अवसर पर शाजापुर विधायक श्री अरुण भीमावद, कालापीपल विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमराज सिंह सिसोदिया, प्रमुख सचिव वन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री शुभरंजन सेन, मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक डॉ. समिता राजौरा, उज्जैन संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, एडीजी श्री राकेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक डॉ. किरण बिसेन, कलेक्टर डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े, पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला, प्रधान रेस्क्यू एवं ट्रांसलोकेशन अभियान की नोडल अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्रामीणजन मौजूद थे।

ओमप्रकाश बनेंगे आनंद संस्थान के सीईओ

मोहन सरकार ने सौंपा जिम्मा, सीएम ऑफिस में बने रहेंगे राजेश हिंगणकर

भोपाल। नर्मदा परिक्रमा कर चुके रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव को मोहन सरकार ने राज्य आनंद संस्थान का सीईओ बनाया है। वहीं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार हिंगणकर को एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें एक साल के लिए संविदा सेवा वृद्धि दी गई है। मोहन कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में आनंद विभाग की ओर से ओमप्रकाश श्रीवास्तव को राज्य आनंद संस्थान के सीईओ पद पर संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव लाया गया था। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग इसके आदेश जारी करेगा। ओमप्रकाश श्रीवास्तव शिवपुरी, रीवा समेत कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं। उन्होंने गृह विभाग के सचिव, आबकारी आयुक्त और जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी भी निभाई है। श्रीवास्तव ने पिछले साल अपनी पत्नी के साथ नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा वे साहित्यिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। राज्य सरकार ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार हिंगणकर को एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के पद पर संविदा नियुक्ति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हिंगणकर 1 नवंबर 2026 से एक साल तक ओएसडी के रूप में काम करते रहेंगे। हिंगणकर की ओएसडी पद पर संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें 4 दिसंबर 2024 को जारी आदेश के अनुसार प्रभावी रहेंगी।

राजधानी में दिवाली पर रहेगी जबरदस्त सख्ती

पटाखा दुकानों के पास तैनात रहेंगी फायर टीमें

भोपाल। दिवाली पर पटाखों की खरीदारी और आतिशबाजी के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। पटाखा बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अग्निशमन वाहन व प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहेंगे। बिजली के तारों और ट्रांसफॉर्मर के आसपास पटाखा दुकान लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और ऊर्जा विभाग ने त्योहार के दौरान आग और बिजली से जुड़े हादसों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को पटाखा बिक्री स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। बाजारों में बिजली के खुले तारों और ओवरलोडिंग की जांच भी होगी। प्रशासनिक टीमें दुकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पटाखा कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिजली की लाइन या ट्रांसफॉर्मर के नीचे और उनसे सटाकर दुकानें नहीं लगाई जाएं। दुकानों में रोशनी के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली इस्तेमाल करने और सीधे तार डालकर बिजली लेने पर कार्रवाई हो सकती है। आतिशबाजी के दौरान भी बिजली के खंभों, तारों और ट्रांसफॉर्मर से दूरी बनाए रखना जरूरी है। पटाखों की चिंगारी से बिजली के उपकरणों में आग लगने या अन्य हादसे का खतरा रहता है।

बाजारों में पांच व्यवस्थाओं पर रहेगा जोर- पटाखा बिक्री स्थलों पर अग्निशामक यंत्र, पानी और रेत की व्यवस्था रखनी होगी। दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी और आने-जाने के रास्ते खुले रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में दमकल वाहन और बचाव दल आसानी से पहुंच सकें। बिजली कनेक्शन की जांच के साथ स्वीकृत लोड से अधिक खपत पर भी नजर रखी जाएगी।

हलालपुरा की आग ने बढ़ाई थी चिंता

भोपाल के हलालपुरा क्षेत्र में पटाखा दुकान और गोदाम में आग लगने के दौरान लगातार धमाके हुए थे। आग की लपटें करीब 70 फीट तक उठी थीं। आग बुझाने के लिए आसपास की बिजली आपूर्ति भी बंद करनी पड़ी थी। इसके अलावा अप्रैल 2017 में इंदौर के रानीपुरा में पटाखा दुकान में आग से पांच लोगों की मौत हुई थी। जून 2017 में बालाघाट की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 25 लोगों की जान गई थी। अक्टूबर 2022 में मुरैना के बानमोर में पटाखे रखने और बनाने के दौरान हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत हुई और छह घायल हुए थे। इन हादसों को देखते हुए त्योहार के दौरान पटाखा बाजारों में सुरक्षा नियमों का पालन और समय रहते जांच को अहम माना जा रहा है।

समस्याओं के हल के लिए सदन पहुंचें मुस्लिम

- **शाही इमाम बोले-सियासत में भागीदारी से ही सभी मसले हल होंगे**
- **रहमानी बोले-सड़क पर प्रदर्शन से एफआईआर होगी, समाधान नहीं**

भोपाल। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के स्थायी समाधान के लिए राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी होगी। मस्जिदों से जुड़े कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) और दूसरे मुद्दों पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने के लिए समाज के लोगों का विधानसभा और संसद तक पहुंचना जरूरी है। सड़क पर प्रदर्शन करने से एफआईआर हो सकती है, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए कानून बनाने वाली संस्थाओं में भागीदारी अहम है। मौलाना बुधवार को भोपाल में कस्तूरबा शिक्षा समिति के एएम हायर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी, वक्फ बोर्ड की नई बॉडी में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, सामाजिक एकता और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की राजनीतिक रणनीति पर अपनी बात रखी।

फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल हों

भोपाल में वक्फ बोर्ड की नई बॉडी में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के सवाल पर मौलाना ने कहा कि मुस्लिम समाज की परेशानी की एक बड़ी वजह राजनीतिक भागीदारी की कमी है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रतिनिधि कानून बनाने वाली संस्थाओं में पहुंचेंगे, तो संबंधित कानूनों और व्यवस्थाओं पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। मस्जिदों में अजान से जुड़े नियमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल मुतवल्ली की भूमिका नहीं होती, बल्कि संबंधित संस्थाओं और कानून बनाने वाली व्यवस्था के फैसले भी महत्वपूर्ण होते हैं।

जाति-बिरादरी और अहंकार से कमजोर हुई एकता

मौलाना ने मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद मतभेदों पर चिंता जताते हुए कहा कि जाति, बिरादरी और अहंकार के कारण समाज की एकता कमजोर हुई है। लोग अपने धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व की अच्छाइयों को देखने के बजाय उनकी कमियां तलाशने में लगे रहते हैं। इससे समाज छोटे-छोटे समूहों में बंट जाता है और उसकी सामूहिक ताकत प्रभावित होती है। उन्होंने कुरान की उस शिक्षा का उल्लेख किया, जिसमें आपसी फूट से बचने और एकजुट रहने की बात कही गई है। मौलाना ने कहा कि समाज को दूसरों को दोष देने के साथ अपनी कमजोरियों पर भी विचार करना चाहिए। आपसी मतभेद दूर किए बिना बड़े सामाजिक उद्देश्यों को हासिल करना मुश्किल है। मौलाना ने कहा कि समाज की तरक्की के लिए धार्मिक शिक्षा के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना जरूरी है। पैगंबर साहब की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती भी महत्वपूर्ण हैं। नमाज के साथ जकात की अनिवार्यता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना सामाजिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। मुस्लिम समाज को शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आपसी एकता और राजनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पैगंबर साहब ने दूसरे समुदायों से किया था संवाद

मौलाना ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद के प्रसंग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वहां अमन और सुरक्षा के इंतजामों के लिए दूसरे समुदायों के साथ संवाद और समझौते किए गए। उनके मुताबिक, यह उदाहरण बताता है कि समाज के हितों और सुरक्षा के लिए राजनीतिक समझदारी तथा दूसरे समुदायों के साथ सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस देश में हम रहते हैं, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी के जरिए ही अपने अधिकारों और हितों को प्रभावी ढंग से सामने रखा जा सकता है। समाज को राजनीति से दूरी बनाने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपनी मौजूदगी मजबूत करनी चाहिए।

एक्टिवा-जूपिटर से शराब की सप्लाई, घेराबंदी कर दबोचा

भोपाल में होटल, रेस्टोरेंट-ढाबों पर कार्रवाई, 10 से ज्यादा केस दर्ज

भोपाल। भोपाल में एक्टिवा और जूपिटर से शराब की सप्लाई करने पर आबकारी विभाग ने दो लोगों को पकड़ा है। इनके पास से अवैध शराब जब्त की गई। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी सर्चिंग की गई। इस दौरान अवैध शराब पिलाने के 10 से ज्यादा केस बनाए गए। यह कार्रवाई मंगलवार-बुधवार की रात हुई। आबकारी कंट्रोलर वर्षा उइके ने बताया कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैन व टीम ने घोड़ा नक्काश निवासी चंचल साहू को एक्टिवा से अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए पकड़ा। इसके बाद उसके घर की तलाशी लेने पर 15 बोतल विदेशी शराब भी मिली। इसी तरह सहायक जिला आबकारी अधिकारी शरद मिश्रा व टीम ने पीएंडटी चौराहा के पास से जूपिटर से अवैध शराब की सप्लाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रीति उइके ने बैरागढ़ क्षेत्र के एवं उप निरीक्षक स्वाति बघेल ने करोंद क्षेत्र में संचालित होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर सर्चिंग की। यहां संचालक और शराब के अवैध सेवन पर 10 से अधिक केस बनाए गए।

करवा चौथ आज, सबसे पहले सिंगरौली में दिखेगा चांद

राजधानी में 8.26 और इंदौर में 8.34 बजे होंगे दीदार

भोपाल। आज गुरुवार को करवा चौथ पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। रात में चांद देखकर व्रत पूरा करेंगी। हालांकि इस बार चक्रवात 'अर्नब' की वजह से चांद का दीदार मुश्किल हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक एमपी में सबसे पहले रात 8.01 बजे सिंगरौली में चांद दिखेगा। जबकि सबसे आखिरी में आलीराजपुर में रात 8.41 बजे नजर आएगा। भोपाल में रात 8.26 बजे और इंदौर में रात 8.34 बजे चांद का दीदार होगा।

करवा चौथ के दिन पूर्वी हिस्से- जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं, पश्चिमी हिस्से- भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम्, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में बादल छाए रह सकते हैं। इस वजह से इंतजार लंबा हो सकता है। नेशनल अवॉर्डी विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर बताया कि चंद्रमा की गति पूर्व से पश्चिम की ओर होने के कारण चांद सबसे पहले मध्य प्रदेश के सुदूर पूर्वी छोर पर मुस्कुराएगा, जबकि पश्चिमी सीमा पर बसे जिलों में अर्घ्य देने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के बीच चंद्रोदय के समय में लगभग 40 मिनट का अंतर दर्ज होगा।

चंद्रोदय के समय में लगभग 40 मिनट का अंतर

घारू ने बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार काफी बड़ा है। जो जिले देशांतर रेखा के अनुसार सुदूर पूर्व में हैं, वहां पृथ्वी के घूमने के कारण चंद्रमा क्षितिज पर सबसे पहले दिखाई देता है। जैसे-जैसे पृथ्वी आगे घूमती जाती है, वैसे-वैसे पश्चिम में स्थित जिलों में चंद्रमा क्रमशः बाद में दिखाई देता है। सिंगरौली से आलीराजपुर के बीच देशांतरीय अंतर के कारण ही प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच चंद्रोदय के समय में लगभग 40 मिनट का अंतर आ जाता है।

कई जगहों पर तय समय से 10-15 मिनट लेट

सारिका घारू ने बताया कि दिया गया चंद्रोदय का समय क्षितिज से उदित होने का है। अगर आपके क्षेत्र में ऊंची इमारतें, पहाड़ियां या आसमान में हल्के बादल या कोहरा हुआ तो वास्तविक रूप से आंखों से चांद देखने में तय समय से 10-15 मिनट की देरी हो सकती है। सारिका ने कहा कि इस समय चक्रवात के कारण कई जगहों पर बादल रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाएं जिले के चंद्रोदय के समय के बाद पूर्व उत्तर दिशा में चंद्रमा की उपस्थिति मानकर अर्घ्य दे सकती हैं। करवा चौथ के लंबे व्रत की शुरुआत से पहले सुबह-सुबह एक खास रस्म निभाई जाती है, जिसे सरगी कहते हैं। ये सरगी सास की ओर से बहू को दी जाती है। सरगी की थाली में फल, मिठाई, मेवे और फेनी जैसी चीजें रखी जाती हैं। इस परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। सरगी की थाली में वो सभी जरूरी चीजें होती हैं, जो व्रत में आपके काम आती हैं। जो दिन भर भूखे रहने के दौरान शरीर को ऊर्जा देती हैं। महिलाएं गणेश जी, चौथ माता और चंद्र देव की पूजा करती हैं। रात में चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ्य दिया जाता है। चंद्र दर्शन और पूजा के बाद ही खाना-पानी ग्रहण कर व्रत खोला जाता है।

इस व्रत में करवा चौथ माता की कथा सुनना या पढ़ना जरूरी होता है। बिना इसके व्रत पूरा नहीं माना जाता।

भोपाल में आगजनी के बाद जागा प्रशासन

आईएसबीटी में लगेंगे फायर हाइड्रेंट, महीनों से खड़ी बसें हटेंगी, और कई बदलाव

भोपाल। आगजनी की घटनाओं के बाद अब प्रशासन ने बस टर्मिनस की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू की है। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आईएसबीटी) में आग से बचाव के लिए फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे और बिजली की वायरिंग की जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही परिसर में लंबे समय से खड़ी गैर संचालित बसों को हटाने और उनके संचालकों से किराया वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने आईएसबीटी का निरीक्षण कर सुरक्षा, सफाई और बसों के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार करने को कहा। आईएसबीटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फायर हाइड्रेंट स्थापित करने के निर्देश दिए

हैं। इसके साथ ही परिसर में बिजली की वायरिंग की जांच कराई जाएगी, ताकि संभावित खतरों की पहचान कर जरूरी सुधार किए जा सकें। परिसर की नियमित साफ-सफाई और व्यापक स्तर पर धुलाई कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

साइकिल और ई-बाइक चलाने के लिए निकलेगा टेंडर

आईएसबीटी परिसर में रखी साइकिलों और इलेक्ट्रिक साइकिलों का संचालन शुरू कराने की तैयारी भी की जा रही है। निगम इन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर चलाने के लिए निविदाएं जारी करेगा। निगम आयुक्त ने कहा कि वे स्वयं इन साइकिलों और ई-बाइक का परीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने वर्मा ट्रेवल्स के मैनेजर से चर्चा की और गैर संचालित बसों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईएसबीटी से बसों का संचालन करने वाली अन्य ट्रैवल्स एजेंसियों के संचालकों के साथ भी बैठक की जाएगी।